नई दिल्ली ■ गुरुवार 26 मार्च 2026 ■ मूल्य 5.00 ■ वर्ष 13 ■ अंक 357 ■ पृष्ठ 08

JBT जनभावना टाइम्स

www.thejbt.com

निष्पक्ष और निर्भीक खबर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गौतमबुद्ध नगर, देहरादून, लखनऊ, अलीगढ़, मथुरा, हिसार, कैथल एवं करनाल से प्रकाशित

04 निजी स्कूलों की महंगी फीस, बड़े दावे और हकीकत | 07 तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करें पंत : फाफ डु प्लेसी | बॉलीवुड पर बरसीं अमीषा पटेल 08

केंद्र ने आईवीएफआरटी योजना को 2031 तक बढ़ाने को मंजूरी दी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने इमिग्रेशन, वीजा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन और ट्रैकिंग (आईवीएफआरटी) योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर 1,800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को यहां पत्रकारों को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने आईवीएफआरटी 3.0 योजना को 31 मार्च के बाद अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है। यह योजना अब एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी। इसके लिए 1800 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। उन्होंने कहा कि आईवीएफआरटी 3.0 का उद्देश्य वैध विदेशी यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाना और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करना है। इसके तहत तीन प्रमुख घटकों पर काम किया जाएगा, जिनमें उभरती तकनीकों का उपयोग, बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण और सेवाओं का अनुकूलन शामिल है। उन्होंने बताया कि आईवीएफआरटी 3.0 के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधार आधारित पहचान, चेहरे की पहचान और आंख की पुतली पहचान जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे सिस्टम के मुख्य ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा।

वैष्णव ने कहा कि पहले सभी सिस्टम अलग-अलग थे, लेकिन अब उन्हें एकीकृत कर दिया गया है। नई व्यवस्था में जरूरत पड़ने पर किसी व्यक्ति से संबंधित जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध हो सकेगी, जिससे कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। सरकार के अनुसार इस योजना के तहत देशभर में 117 इमिग्रेशन पोस्ट, 15 विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी और 850 से अधिक विदेशी पंजीकरण अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपायुक्त कार्यालय जुड़े हुए हैं। पिछले वर्षों में इस सिस्टम के जरिए 91 प्रतिशत से अधिक ई-वीजा आवेदन 72 घंटे के भीतर निपटाए गए हैं। इसके अलावा 13 बड़े हवाई अड्डों पर लागू फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम के जरिए यात्रियों का इमिग्रेशन क्लियरेंस समय घटकर 30 सेकंड रह गया है। इसका एनरोलमेंट अभी भारतीय नागरिकों और ओसीआई कार्डहोल्डर्स के लिए फ्री बेसिस पर उपलब्ध है। सरकार का मानना है कि इस योजना से पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

कार्बन उत्सर्जन में 2035 तक 47 प्रतिशत कटौती का लक्ष्य, केंद्र ने नए एनडीसी को दी मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैश्विक पर्यावरण से जुड़ा एक प्रमुख नीतिगत फैसला लिया है। सरकार ने 2026 पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को औपचारिक मंजूरी दे दी है। यह फैसला वैश्विक मंच पर भारत की कार्बन उत्सर्जन कम करने की प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट करता है और भविष्य में ग्रीन एनर्जी तथा सतत विकास से जुड़ी कॉर्पोरेट रणनीतियों को एक नई दिशा देगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत भारत ने अपने जलवायु लक्ष्यों को और मजबूत करते हुए 2031–2035 अवधि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को मंजूरी दी है।

क्षेत्रीय संपर्क योजना 'उड़ान' 2.0 को मंजूरी दी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना 'उड़ान' के संशोधित संस्करण (उड़ान 2.0) को मंजूरी दे दी। इस योजना के लिए 28,840 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक 10 वर्षों के लिए लागू होगी, जिसका लक्ष्य 100 नए हवाई अड्डों/हेलीपोर्ट को विकसित करना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।

पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर सर्वदलीय बैठक

प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध जल्द खत्म करने पर दिया जोर

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत में इस बात पर जोर दिया कि पश्चिम एशिया में युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए क्योंकि इससे सभी को नुकसान हो रहा है।

सूत्रों का कहना है कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष में कथित मध्यस्थता के संदर्भ में पाकिस्तान को 'दलाल' राष्ट्र करार दिया। सूत्रों के अनुसार, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में कहा कि इस मामले में पाकिस्तान के मध्यस्थता प्रयासों में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि उस देश का 1981 से अमेरिका द्वारा 'इस्तेमाल' किया जा रहा है। यह जानकारी मिली है कि जयशंकर ने पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा के लिए संसद परिसर में बुलाई गई बैठक में उपस्थित नेताओं से कहा कि हम दलाल राष्ट्र नहीं हैं।

सूत्रों के अनुसार, सरकार ने विपक्ष के इस आरोप का खंडन किया कि भारत सरकार इस मामले पर चुप है और कहा कि 'हम टिप्पणी कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं।' सरकार का पक्ष था कि जब ईरान दूतावास खोला गया, तो विदेश सचिव ने तुरंत वहां दौरा किया और शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने पर जल्द शोक व्यक्त न करके नैतिक कमजोरी दिखाई है। बताया जाता है कि सरकार ने राजनीतिक दलों को यह भी सूचित किया है कि उसकी मुख्य चिंता खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और घरेलू ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है।

उस संबंध में सरकार ने कहा कि वह अब तक सफल रही है। पश्चिम एशिया संकट पर सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्ष ने कहा कि इस मामले से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं था। उन्होंने यह मांग फिर दोहराई कि लोकसभा में नियम 193 और राज्यसभा में नियम 176 के तहत पश्चिम एशिया संकट को लेकर चर्चा होनी चाहिए। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार की ओर से स्पष्टीकरण देने की कोशिश हुई जो संतोषजनक नहीं है। हम लोगों की मांग है कि लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद लोगों को संतुष्टि होगी।

उनका कहना था कि बहुत सारे मुद्दे थे, जिन पर सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं था।

गुजरात विस में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, देश का दूसरा राज्य बना

गांधीनगर। गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक आज बहुमत से पारित हो गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के बाद गुजरात यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है।

बिल पारित होने के बाद सदन में सत्तापक्ष के सदस्यों ने समर्थन जताते हुए 'जय श्री राम' के नारे लगाए और मेज थपथपाकर स्वागत किया। सदन में बिल के विरोध में विपक्षी सदस्यों ने सवाल उठाएं। वहीं सत्तापक्ष के सदस्यों ने इस बिल को समानता, न्याय और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाला बताया। गुरुवार को विधानसभा में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। जिसके बाद सदन में 7 घंटे में लंबी चर्चा हुई। चर्चा के दौरान हलाला प्रथा, शाह बानो केस, अभिनेता धर्मेंद्र के दूसरे विवाह और श्रद्धा वाकर जैसे मामलों का भी उल्लेख किया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह कानून समानता, न्याय और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में पुरखों से शादी एक परंपरा है, लेकिन इस बिल का कानून माइनॉरिटी कम्युनिटी पर लागू नहीं होगा। हम बराबरी, न्याय और एकता के राष्ट्रीय संकल्प को मजबूत करेंगे। हमारे देश की संस्कृति हमें परिवार की भावना सिखाती है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात के लिए सतर्क है कि जातिगत भेदभाव न हो। शादी का जरूरी रजिस्ट्रेशन, तलाक़ के एक जैसे नियम, पेनल्टी समेत कुछ जरूरी प्रॉविज़न होंगे। शादी का रजिस्ट्रेशन न कराने वालों को सज़ा देने का प्रॉविज़न है।

उन्होंने कहा कि राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होगा। जो लोग अपनी शादी रजिस्टर नहीं करवाएंगे, उन पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगेगा और एक से ज्यादा बार शादी करने वालों को चार साल की जेल होगी।

सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर

नई दिल्ली। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को मंगलवार रात पेट में इंफेक्शन की शिकायत के बाद दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। बुधवार को अस्पताल द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, सोनिया गांधी को मंगलवार रात 10:22 बजे सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के चेयरमैन डॉ अजय स्वरूप ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि डॉक्टर उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टरों द्वारा उनकी विस्तृत जांच की जा रही है, जिसमें पेट और यूरिनरी ट्रैक में संभावित संक्रमण की जांच भी शामिल है। इलाज के तहत उन्हें एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं। अस्पताल की एक विशेषज्ञ टीम उनकी निगरानी कर रही है और आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा रही है।

पाकिस्तान के बयान को भारत ने किया खारिज, आतंकवाद पर घेरा

नई दिल्ली। भारत ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े न्यायिक मामलों पर पाकिस्तान के बयान को सख्ती से खारिज किया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को मीडिया के सवालों पर कहा कि भारत पाकिस्तान द्वारा जारी इस बयान को पूरी तरह अस्वीकार करता है, जिसमें एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन और उसके सदस्यों का समर्थन किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों या न्यायिक प्रक्रियाओं पर टिप्पणी करने का पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है।

यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एक ऐसा देश, जो लंबे समय से आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, इस तरह का बयान दे रहा है, जो हिंसा और निर्दोष लोगों की हत्या को उचित ठहराता है। प्रवक्ता ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि झूठ और भ्रामक बयानबाजी करने के बजाय उसे अपने यहां हो रहे गंभीर और व्यवस्थित मानवाधिकार उल्लंघनों पर आत्ममंथन करना चाहिए।

तेलंगाना : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टी. जीवन रेड्डी ने दिया इस्तीफा

हैदराबाद। तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टी. जीवन रेड्डी ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी नेताओं द्वारा मनाने के सभी प्रयास विफल रहे। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के साथ-साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की सदस्यता भी छोड़ दी। रेड्डी ने एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में अपने इस्तीफे के पीछे के कारणों का विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि जगतियाल विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे अन्याय और मानसिक पीड़ा को सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यह निर्णय लिया।

आंध्र प्रदेश में आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 12 संदिग्ध गिरफ्तार

हैदराबाद/विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश पुलिस ने अंतरराज्यीय स्तर पर चलाए गए एक बड़े संगठित अभियान में संदिग्ध आतंकी संबंधों वाले 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में हैदराबाद की एक 35 वर्षीय महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, हैदराबाद के चंचलगुडा रोड स्थित जायका होटल के पास रहने वाली सईदा बेगम पर देशविरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस सेल और विजयवाड़ा पुलिस की संयुक्त टीम ने हैदराबाद पुलिस की मदद से उसके घर पर छापेमारी कर पहले हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे विजयवाड़ा ले जाया गया। हैदराबाद पश्चिम जोन के एसीपी एन.एस.वी.के. दुर्गा राव ने बताया कि सईदा बेगम की गिरफ्तारी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों के तहत की गई है।

दिल्ली के अक्षरधाम में 108 फीट ऊंची श्री नीलकंठ वर्णी प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा आज

गांधीनगर। दिल्ली का स्वामिनारायण अक्षरधाम देश की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय धरोहर के रूप में पूरे विश्वभर में प्रसिद्ध है। 26 मार्च को यह एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है।

वैश्विक बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) संस्था के प्रमुख महंतस्वामी महाराज के कर-कमलों द्वारा तपोमूर्ति श्रीनीलकंठवर्णी (भगवान स्वामिनारायण) की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा की जाएगी। पंचधातु से निर्मित यह प्रतिमा दुनिया की ऐसी पहली विशाल प्रतिमा है, जो भगवान के कठिन तप को दर्शाते हुए 'एक चरण' पर अडिग खड़ी है। इस आयोजन की भव्य तैयारियां जोरों पर है। महंतस्वामी महाराज 19 मार्च को दिल्ली पधारे। उनके स्वागत में 21 मार्च को एक विशिष्ट स्वागत सभा का आयोजन किया गया। 22 मार्च रविवार की सुबह पंचकुला और कुरुक्षेत्र में नवनिर्मित बीएपीएस स्वामिनारायण मंदिरों की मूर्ति प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही स्वामी के सान्निध्य में सभी भक्तों नें फूलों की होली के उत्सव का अद्भुत लाभ लिया।

23 मार्च को आगामी सितम्बर में पेरिस मंदिर में प्रतिष्ठित होने वाली मूर्तियों का पूजन किया गया। तपोमूर्ति श्रीनीलकंठवर्णी भगवान भगवान स्वामिनारायण ने मात्र 11 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर 7 वर्ष तक संपूर्ण भारत में लोक कल्याण के लिए यात्रा की।

12,000 किलोमीटर से भी अधिक की इस कठिन आध्यात्मिक यात्रा में उन्होंने उत्तर में हिमालय, बदरीनाथ-केदारनाथ, कैलाश-मानसरोवर, नेपाल में मुक्तिनाथ, पूर्व में कामाख्या देवी मंदिर, ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, नासिक, पंढरपुर, पश्चिम में द्वारका आदि तीर्थों को अपनी चरणधूलि से पावन किया। उनकी इस अद्भुत यात्रा के दौरान उन्होंने 'नीलकंठ वर्णी' नाम धारण किया।

महिला सुरक्षा: पुलिस कमिश्नर ने किया पिंक बूथ का उद्घाटन

नोएडा। जनपद गौतमबुद्ध नगर में प्रदेश सरकार के निर्देश पर महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, जागरूकता एवं त्वरित पुलिस सहायता के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति-5.0 (द्वितीय चरण) कार्यक्रम के तहत पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बुधवार को थाना बिसरख क्षेत्र के गौर सिटी-2, नियर महागुन मायवुड्स सोसाइटी व चौकी क्षेत्र राइज चौक के अंतर्गत नियर इको विलेज-1 सोसाइटी में स्थित नवनिर्मित 2 पुलिस पिंक बूथ का उद्घाटन किया गया। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में यह 28 और 29 पिंक बूथ है। यह पिंक बूथ ऐसे स्थानों पर स्थापित किए गए हैं जहां महिलाओं की आवाजाही अधिक रहती है। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि पुलिस पिंक बूथ का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराना है। इस बूथ पर महिला पुलिसकर्मी ही तैनात होगीं। जिससे शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं को अपनी परेशानी बताने में किसी प्रकार की हिचक महसूस ना हो। उन्होंने कहा कि मुख्य स्थान पर पिंक बूथ के होने से कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के मन में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। कार्यक्रम के दौरान पुलिस कमिश्नर ने उपस्थित महिलाओं व छात्राओं से निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने छात्राओं को बताया गया कि वह किसी भी अपराध को चुपचाप सहन न करने और किसी भी परिस्थिति में वह पिंक बूथ पर तुरन्त पुलिस सहायता प्राप्त कर सकती है। इन बूथ पर महिला पुलिसकर्मी को अपनी परेशानी बताने में किसी प्रकार की हिचक महसूस ना हो। कार्यक्रम के दौरान पुलिस कमिश्नर ने उपस्थित सभी बच्चों को अध्ययन सामग्री (बैग, किताबें, पानी की बोतल, टिफिन आदि) वितरित की गई।

कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय अजय कुमार, डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी, प्रभारी डीसीपी महिला सुरक्षा अनुकृति शर्मा, एडीसीपी आरके गौतम, एसीपी द्वितीय सेंट्रल नोएडा पवन कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। बता दें कि मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत महिला पुलिसकर्मियों द्वारा प्रतिदिन सभी थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहते हुए विभिन्न सोसाइटियों, स्कूलों, कंपनियों, मैट्रो स्टेशन, बस स्टैण्ड व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाकर महिलाओं को आत्मसुरक्षा व साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण अभियान, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के संबंध में जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन के संबंध में शासन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे मिशन शक्ति फेस-5.0, शुभ मंगल योजना, साइबर क्राइम एवं साइबर सुरक्षा की जानकारी प्रदान की जाती है। महिलाओं व छात्राओं को महिला हेल्पलाइन नंबर-1090, आपातकालीन सेवा-112, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर-1098, वन स्टॉप सेंटर नंबर-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर-1076 व साइबर हेल्पलाइन नंबर-1930 के बारे में प्रतिदिन जानकारी दी जा रही है।

एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज 3.26 करोड़ की ठगी में 15वां शातिर ठग गिरफ्तार

नोएडा। थाना साइबर क्राइम पुलिस ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर मोटा लाभ कमाने का झांसा देकर 3.26 करोड़ रुपए की ठगी करने के मामले में आज एक आरोपी को एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायतों में प्रयुक्त संदिग्ध मोबाइल नंबरों की तकनीकी जांच व लोकल इंटेलीजेंस की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त दो मोबाइल फोन बरामद किया है। इस ठगी के मामले में पुलिस पूर्व में 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

एडीसीपी साइबर क्राइम शैव्या गोयल ने बताया कि थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक सूचना के आधार पर बुधवार को बंटी कुमार पुत्र कमलदेव पोद्दार उम्र 32 वर्ष मूल निवासी जनपद पूर्णिया बिहार को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इसके पास से पुलिस ने दो मोबाइल फोन बरामद किया है। उन्होंने बताया कि इन बदमाशों ने एक व्यक्ति को अपने जाल में फंसाकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पर उनसे 3 करोड़ 26 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। आरोपी के खाते में ठगी की रकम ट्रांसफर हुई थी। इसके खाते से ठगी से संबंधित 60 लाख रुपए की रकम प्राप्त हुई थी। इस खाते के संबंध में 1 शिकायत एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि अभियोग से संबंधित 14 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

तीन बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा। कंपनी और घरों में चोरी करने वाले गैंग के सरगना समेत तीन बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर ऐक्ट में कार्रवाई की। हाल ही में इस गैंग को गिरफ्तार किया गया था।

ईकोटेक तीन कोतवाली प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि हाथरस निवासी गगन उर्फ जीनू उर्फ शिवम, मनी उर्फ अमन कुमार और संभल निवासी सुहेल उर्फ गोलू के खिलाफ गैंगस्टर ऐक्ट की कार्रवाई की गई। बदमाश गगन इस गैंग का सरगना है। जेल में बंद गगन पर 10 मुकदमे दर्ज हैं।

इसके अलावा मनी और सुहेल के खिलाफ छह-छह मुकदमे दर्ज हैं। यह गिरोह बंद घरों और कंपनियों की रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके खिलाफ गैंगस्टर ऐक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है।

फ्लैट से लैपटॉप और सामान चोरी

नोएडा। सेक्टर-39 थानाक्षेत्र स्थित एक फ्लैट से चोर लैपटॉप समेत अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित अरहन जैन ने पुलिस को बताया कि वह अपने दोस्त अभिषेक और आर्य के साथ सेक्टर-46 स्थित फ्लैट में रहते हैं। 22 मार्च की सुबह सात से साढ़े सात बजे के बीच दरवाजा खुला रह जाने का फायदा उठाकर अज्ञात चोर फ्लैट में घुस गया। वहां रखे तीन लैपटॉप और अन्य सामान चोरी कर लिया। चोरी हुए सामान में अभिषेक शर्मा का पासपोर्ट भी शामिल है।

बाइक सवार बदमाश ने युवती की चेन लूटी

नोएडा। सेक्टर-20 थानाक्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवती के गले से 15 ग्राम की सोने की चेन झपट ली। सेक्टर-27 निवासी गुंजन चावला ने पुलिस को बताया कि 13 मार्च को दोपहर दो बजे वह डी-ब्लॉक मार्केट से इंद्रा मार्केट की ओर जा रही थीं। इंडसइंड बैंक के पास सड़क पार करते समय पीछे से बाइक सवार दो बदमाश आए और उनके गले से सोने की चेन और लॉकेट छीनकर फरार हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी गलत दिशा में सेक्टर-19 की ओर भाग निकले।

तमंचे के साथ बदमाश गिरफ्तार

नोएडा, 25 मार्च (वेब वार्ता)। वारदात की फिराक में घूम रहे बदमाश को एक्सप्रेसवे थाने की पुलिस ने बुधवार को थानाक्षेत्र से ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान बिहार के सहरसा निवासी सिराजुल खान के रूप में हुई है। वर्तमान में वह वाजिदपुर गांव में किराए का कमरा लेकर रह रहा है। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से तमंचा और कारतूस मिला। आरोपी के खिलाफ दो केस पहले से ही विभिन्न धाराओं में एक्सप्रेसवे थाने में दर्ज हैं। अन्य थानों से भी उसका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है।

जेवर एयरपोर्ट को एसपीजी ने लिया सुरक्षा घेरे में, तैयारियां अंतिम चरण में

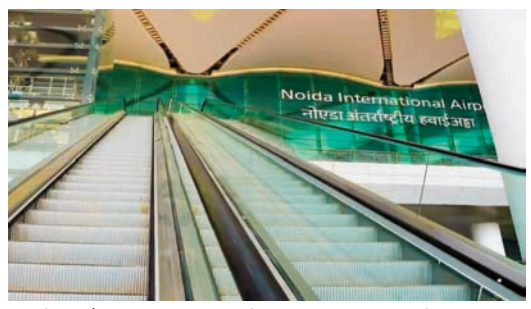

नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 28 मार्च को होने वाले लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गईं हैं। पीएम मोदी द्वारा होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी व्यवस्था को अमली जामा पहनने में जुट गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी ने पूरे एयरपोर्ट परिसर को अपनी सुरक्षा में ले लिया है। वहां पर बिना एसपीजी के अनुमति के किसी को भी आने-जाने को अनुमति नहीं दी जा रही है। मीडिया को भी अब एयरपोर्ट परिसर से सुरक्षा कारणों से दूर रखा जा रहा है। बिना अनुमति के कोई भी मीडियाकर्मी अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है।

जिला सूचना निदेशक सुनील कुमार कनौजिया ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में की गई समीक्षा के बाद सभी विभाग अपनी जिम्मेदारियों को अंतिम रूप देने में लग गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, मार्ग संचालन, चिकित्सा सुविधा, अग्निशमन, विद्युत आपूर्ति, साफ-सफाई, पेयजल, बैरिकेडिंग, साइनेज और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम सहित सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड, पार्किंग और आगमन-प्रस्थान मार्गों को पूरी तरह व्यवस्थित किया जा चुका है, वहीं ट्रैफिक सुचारु बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी बढ़ाई गई है और कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वीवीआईपी, जनप्रतिनिधियों, उद्यमियों अधिकारियों और आमजन की संभावित बड़ी संख्या को देखते हुए साफ-सफाई, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को निवेश, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को गति देगा। प्रशासनिक स्तर पर लगातार निगरानी के साथ यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यह ऐतिहासिक लोकार्पण कार्यक्रम पूरी तरह सुव्यवस्थित और सफलतापूर्वक संपन्न हो।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं पल-पल का अपडेट ले रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एयरपोर्ट का निरीक्षण कर सभी तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी प्रदान किए।

रन फॉर एम्पॉवरमेन्ट का आयोजन प्रतिभागियों को किया सम्मानित

नोएडा। सेक्टर-21ए स्थित नोएडा स्टेडियम में मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण के अंतर्गत रन फॉर एम्पॉवरमेन्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 200 छात्राएं एवं कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की लगभग 150 महिला पुलिस कर्मियों ने आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को नकद पुरस्कार, ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। गौतमबुद्धनगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) अजय कुमार तथा पुलिस उपायुक्त महिला एवं बाल सुरक्षा अनुकृति शर्मा के नेतृत्व में मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण के अंतर्गत "रन फॉर एम्पॉवरमेन्ट" कार्यक्रम का आयोजन नोएडा स्टेडियम हुआ।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं में आत्मविश्वास, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, सशक्तिकरण की भावना को बढ़ावा देना तथा समाज में महिला सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति सकारात्मक संदेश प्रसारित करना रहा। कार्यक्रम में पुलिस विभाग एवं विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रतिभागियों की सहभागिता देखने को मिली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पैरा ओलंपिक खिलाड़ी एवं पद्मश्री सम्मानित दीपा मलिक शामिल रही। उनके द्वारा प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए रन फॉर एम्पॉवरमेन्ट की भावना को विस्तारपूर्वक समझाया गया। उन्होंने अपने जीवन संघर्ष, कठिन परिस्थितियों में निरंतर प्रयास, तथा दिव्यांगता के बावजूद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के अपने अनुभव साझा किए।

दीपा मलिक ने कहा कि जीवन में चुनौतियां हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी बाधा सफलता के मार्ग में रुकावट नहीं बन सकती। उन्होंने छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने, मानसिक रूप से मजबूत रहने तथा अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयासरत रहने के लिए प्रेरित किया। रन फॉर एम्पॉवरमेन्ट कार्यक्रम कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों की लगभग 200 छात्राओं एवं कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की लगभग 150 महिला पुलिसकर्मियों द्वारा उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया गया। दौड़ प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर नकद पुरस्कार, ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य प्रतिभागी छात्राओं को भी प्रोत्साहन स्वरूप विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए गए।

प्रीपेड स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को परेशानी, यूपीपीसीएल के मुख्य अभियंता से की वार्ता

नोएडा। नोएडा शहर में बिजली विभाग की प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना से उपभोक्ताओं को हो रही समस्याओं के समाधान के लिए बुधवार को फोनरवा के बैनरतले विभिन्न आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने यूपीपीसीएल के मुख्य अभियंता संजय जैन के साथ एक बैठक की। बैठक में अधीक्षण अभियंता उमेश यादव (कमर्शियल), विवेक कुमार (टेक्निकल) तथा सभी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर उपस्थित रहे।

बैठक में आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने स्मार्ट मीटर से संबंधित समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। फोनरवा अध्यक्ष योगेन्द्र शर्मा ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई मामलों में पैसे कटने के बावजूद घरों की बिजली आपूर्ति बंद हो रही है।महासचिव केके जैन ने कहा कि नई प्रणाली लागू होने के बाद प्रतिदिन नई समस्याएं सामने आ रही हैं। उन्होंने बताया कि कई उपभोक्ताओं की बिजली बिल का भुगतान करने के बावजूद काट दी जाती है। उन्होंने मांग की कि जब तक बिजली आपूर्ति पूरी तरह से सुचारू नहीं हो जाती, तब तक नए स्मार्ट मीटर न लगाए जाएं तथा किसी भी उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति बाधित न की जाए। इसके अतिरिक्त, सेक्टर-18 में बिल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए केवल एक कार्यालय होने के कारण अत्यधिक भीड़ रहती है, जिससे दूरदराज के सेक्टरों के उपभोक्ताओं को कठिनाई होती है। इस पर अधिक शिकायत निवारण केंद्र खोलने की मांग की गई।

आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों द्वारा बताई गई उक्त समस्याएं सुनने के बाद मुख्य अभियंता संजय जैन ने बताया कि नया सिस्टम लागू होने के कारण सर्वर पर अधिक लोड पड़ने से तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हुई थीं, जिससे उपभोक्ता समय पर भुगतान नहीं कर सके और उनकी बिजली आपूर्ति बाधित हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि सिस्टम में निरंतर सुधार किया जा रहा है, जिससे भविष्य में ऐसी समस्याएं न हों। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार की नीति के अनुसार पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और कई जिलों में यह प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब तक सर्वर और सिस्टम पूरी तरह से सुचारू नहीं हो जाते, तब तक नए मीटर लगाने की प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया जाएगा। बिजली आपूर्ति काटने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस विषय में प्रबंध निदेशक से चर्चा कर अस्थायी राहत देने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही, बिल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सेक्टर-18 के अलावा अन्य जगहों पर शीघ्र ही अतिरिक्त एक नया कार्यालय खोला जाएगा।

बैठक के दौरान अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा, महासचिव केके जैन, पवन यादव, विजय कुमार भाटी, अशोक कुमार मिश्रा, देवेंद्र सिंह चौहान, विनोद शर्मा, ओमवीर बंसल,कोशिंदर यादव, अनीता, सत्यनारायण गोयल, वीरेंद्र सिंह, राघवेंद्र दुबे सहित अन्य उपस्थित थे।

छह हजार से अधिक दिव्यांग जनों के जीवन में खुशियों की लहर, स्पार्क मिंडा ग्रुप ने लगाया आठ दिवसीय मेगा कैंप

नोएडा। स्पार्क मिंडा फाउंडेशन द्वारा आयोजित आठ दिवसीय मेगा कैंप के जरिए 6,395 दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण, स्किलिंग और आजीविका का अवसर प्रदान किए गए। स्पार्क मिंडा फाउंडेशन की चेयरपर्सन सारिका मिंडा ने बुधवार को बताया कि स्पार्क मिंडा ग्रुप की कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) शाखा द्वारा 18 से 25 मार्च 2026 के बीच नोएडा स्थित मुख्यालय में दिव्यांग जनों के लिए आठ दिवसीय मेगा कैंप का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस कैंप के माध्यम से 6,395 लोगों को कृत्रिम अंग, आर्थोटिक डिवाइसेज, वॉकर, बैसाखिया, हैड स्टीक, विजुअल और हियरिंग एड जैसे उपकरण उपलब्ध कराए गए।

उन्होंने कहा कि मिंडा ग्रुप अपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत देश के विभिन्न जनपदों से दिव्यांग लोगों को ढूंढ कर उन्हें कृत्रिम अंग प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में करीब तीन प्रतिशत लोग दिव्यांग है। मिंडा ग्रुप का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तथा उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 से अब तक ग्रुप ने 38 हजार से अधिक दिव्यांग जनों को सशक्त बनाया है। इससे पहले कुछ वर्षों में स्पार्क मिंडा ग्रुप ने 1,300 से अधिक दिव्यांग जनों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित किए हैं। बीते एक दशक में ग्रुप ने इंडोनेशिया, वियतनाम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर सहित कई स्थानों पर इस तरह के कैंप आयोजित किए हैं। उन्होंने कहा कि स्पार्क मिंडा फाउंडेशन का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक 50 हजार से अधिक दिव्यांग जनों को जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जाए। इस अवसर पर मौजूद स्पार्क मिंडा ग्रुप के अध्यक्ष अशोक मिंडा ने कहा कि दृष्टि या श्रवण संबंधी बाधाएं किसी व्यक्ति के सपने देखने, योगदान देने और बदलाव लाने की क्षमता को सीमित नहीं करती। स्पार्क मिंडा में हम विविधता, समावेशन, और सामान अवसरों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ताकि हर व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान सके और उसे साकार कर सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए उनके ग्रुप ने जयपुर फुट ,स्किल काउंसलिंग फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंडियन बिजनेस एंड डिसेबिलिटी नेटवर्क आदि के संस्थाओं के साथ साझेदारी की है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से इस पहल को और मजबूत बनाया गया है। उन्होंने कहा कि स्पार्क मिंडा को वर्ष 2024 में नेशनल अवॉर्ड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज से भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि मिंडा कॉरपोरेशन आटोमोटिव कॉम्पोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार करती है। इसका भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। कंपनी की स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। कंपनी की मीडिया प्रभारी निधि खन्ना ने बताया कि स्पार्क मिंडा ग्रुप अपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी को निभाते हुए चेन्नई, नागपुर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र स्थित कई जिलों में बंद कैदियों को भी रोजगार उपलब्ध करवा रहा है।

वे कैदी जेल में रहते हुए ही कंपनी द्वारा जेल के अंदर स्थापित इकाइयों में काम करके रकम कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था दिव्यांग जनों का स्किल्ड डेवलपमेंट भी करती हैं। तथा दिव्यांग उद्योगपतियों को लोन दिलवाने का काम भी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ इस काम मे 30 से ज्यादा सामाजिक संस्थाएं जुड़ी है, जिनके माध्यम से भी विकलांग लोग उनसे संपर्क करते हैं तथा उन्हें हर संभव सहायता दी जा रही है।

गलगोटिया विश्वविद्यालय में यूबीसी के प्रोफेसर का व्याख्यान, उच्च शिक्षा के भविष्य पर वैश्विक संवाद

ग्रेटर नोएडा। गलगोटिया विश्व विद्यालय में एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबियाके प्रोफेसर ने मुख्य वक्तव्य दिया। अपने संबोधन में उन्होंने पिछले तीन वर्षों में उच्च शिक्षा में जेनरेटिव एआई की परिवर्तनकारी यात्रा पर प्रकाश डाला।

सत्र में तेजी से बदलते शैक्षणिक परिदृश्य में शिक्षण, सीखने और संस्थागत बदलाव के उभरते रुझानों पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रोफेसर ने अपने वक्तव्य में बताया कि एआई क्षमताओं में हो रही प्रगति किस प्रकार शिक्षण पद्धतियों और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को प्रभावित कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नई तकनीकों का प्रभावी उपयोग तभी संभव है, जब शिक्षण विधियों में भी समानांतर बदलाव किया जाए। साथ ही विश्वविद्यालयों को तकनीक-प्रधान युग में अपनी भूमिका को पुनर्परिभाषित करने तथा फैकल्टी विकास और क्षमता निर्माण में निवेश करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि इन तकनीकों का जिम्मेदार और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण प्रोफेसर और विद्यार्थियों के बीच संवाद रहा, जिसमें शिक्षा में उभरती तकनीकों के जिम्मेदार उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई।

छात्रों ने भी नैतिक पहलुओं, व्यावहारिक उपयोग और बदलते सीखने के तरीकों को लेकर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर चयनित छात्र टीमों ने एआई-आधारित प्रोजेक्ट्स का लाइव प्रदर्शन भी किया। इन प्रस्तुतियों में उन्नत तकनीकी समाधानों के माध्यम से वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किए गए, जो विश्वविद्यालय में रचनात्मकता, शोध-आधारित सीखने और उद्यमशील सोच को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

अरविंद केजरीवाल का महल देखकर लगा मैं धर्मशाला में रहती हूं : रेखा गुप्ता

प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि 4 हजार गज की जगह पर दूसरा महल बनाने की चल रही थी तैयारी

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा तैयार करवाए गए मुख्यमंत्री निवास की सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा कई गई। इस रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रवेश वर्मा के साथ वह एक दिन इस घर को देखने गई थीं। इस आलीशान जगह को देखकर उन्हें महसूस हुआ कि वह एक धर्मशाला में रहती हैं।

मुख्यमंत्री ने शेर पढ़ते हुए कहा कि दिल्ली वाले कह रहे होंगे कि वो जहर देता तो सबकी नजरों में आ जाता, इसलिए उसने दवा देना बंद कर दिया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि यह चर्चा उस सुनियोजित धोखे की है जिस रिपोर्ट को अरविंद केजरीवाल ने लगातार रोके रखा। आम आदमी बनकर उन्होंने दिल्ली के लोगों को ठगा। वास्तव में वह राजा बनकर दिल्ली वालों को दास समझते थे। शीला दीक्षित के घर में लगे दस एसी को लेकर वह ताने मारते थे, आज अपने घर में पचास एसी लगाने को लेकर वह क्या कहेंगे। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए लेकिन वास्तव में उन्हें सब कुछ चाहिए था। देश में जब लाखों लोग मार रहे थे, दिल्ली में हजारों लोग मार रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल अपना शानदार घर बना रहे थे। उन्होंने अस्पताल बनाने को प्राथमिकता नहीं समझा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में खाना नीचे से ऊपर ले जाने के लिए लिफ्ट लगाई थी। घर में 18 लाख रुपये की कॉफी मशीन लगाई। करोड़ों रुपये सलाहकार को दिए गए। ठेकेदार को चुनकर काम सौंपा गया। उन्हें पता था चीफ इंजीनियर की शक्ति दस करोड़ की है। इसलिए कम राशि में टेंडर निकाला गया ताकि फाइल ऊपर न भेजी जाए। उन्हें बताना चाहिए कि आठ करोड़ का टेंडर कैसे 62 करोड़ तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने कहा केवल अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया, राजेंद्र पाल गौतम, रामनिवास गोयल, इमरान हुसैन, राखी बिडलान आदि ने भी अपने घरों पर करोड़ों रुपये खर्च किए। जनता के साथ उन्होंने गुनाह किया है। मुख्यमंत्री ने इस सीएजी रिपोर्ट को पीएसी में भेजने की मांग की है।

24 घंटे में मिली मुख्यमंत्री निवास को मंजूरी कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के लिए इस घर को तैयार करने में महज 24 घंटे के भीतर मंजूरी दी गई। कोरोना के समय इस फाइल पर अत्यंत महत्वपूर्ण लिखा गया था जबकि 11 साल में किसी अन्य विषय की फाइल पर यह शब्द नहीं लिखा गया। इसके लिए जो उन्होंने टाइप-5 के पुराने बंगले तोड़े जिनमें अधिकारी रहते थे। वहांर बहुत सारे पेड़ काटे गए। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास बनाए जाने से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की जिसमें हरियाली की कमी दिख रही है। उन्होंने बताया कि चीफ इंजीनियर की शक्ति 8 करोड़ तक का टेंडर करने की होती है। इसलिए उन्होंने 7.91 करोड़ का टेंडर किया। बाद में इसकी राशि धीरे-धीरे बढ़ाई गई। दिल्ली में उस समय कोई फैक्ट्री या कारखाना नहीं चल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री के निवास तैयार होता रहा। दूसरा महल बनाने की थी तैयारी प्रवेश वर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा तैयार किए गए निवास के पास ही 4000 गज की जगह पर एक अन्य घर बनाया जाना था। इस पर 25 करोड़ रुपये खर्च कर ढांचा खड़ा कर लिया गया था। लेकिन सरकार बदलने के चलते यह पूरा नहीं हो सका।

अरविंद केजरीवाल को लगता था कि वह कभी हारेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने ऐसा घर बनवाया। उन्हें लगता था कि वह जीवन भर अब इसी घर में रहेंगे। यही वजह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने पर आतिशी को भी यह घर नहीं दिया। लोग मरते रहे, घर बनता रहा प्रवेश वर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने यह घर बनाने के लिए ऐसा समय चुना, जब दिल्ली में हजारों लोग कोरोना से मर रहे थे। ऐसे समय में जब अस्पताल तैयार कर लोगों की जान बचानी थी, अरविंद ने अपने लिए आलीशान घर बनाने पर ध्यान दिया।

हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की बदहाल व्यवस्था को लेकर लगातार टिप्पणी कर रही थी। भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को 787.91 करोड़ रुपये कोविड में लोगों की जान बचाने के लिए दिए, जिसमें से 582 करोड़ रुपये ही उन्होंने खर्च किए। इस राशि से बच सकती थी 2300 जान प्रवेश वर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए घर बनाने में जो 58 करोड़ रुपए खर्च किए, उससे आईसीयू वेंटिलेटर लेते तो कम से कम 2300 जान बच सकती थी। केन्द्र सरकार ने एक आईसीयू बेड की कीमत 15 हजार रुपये कर दी थी। इस राशि से वह 2300 आईसीयू वेंटिलेटर बेड ले सकते थे। दिल्ली में 26 हजार लोग कोरोना में मारे गए। लेकिन उन्होंने इन लोगों की जान बचाने से ज्यादा आवश्यक अपने लिए घर बनाना समझा।

'शीश महल' जनता के साथ विश्वासघात

मंत्री प्रवेश ने सदन में पेश किया खर्चों का प्रिंटिंग पेपर रोल

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बुधवार को कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए तथाकथित 'शीश महल' के निर्माण को लेकर पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर जनता के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया।

उन्होंने सदन में याद दिलाया कि शुरुआत में सादगी का वादा किया गया था..न सरकारी बंगला, न गाड़ी, न सुरक्षा, लेकिन सत्ता में आने के सिर्फ 20 दिनों के भीतर फ्लैगस्टाफ रोड का बंगला आवंटित कर लिया गया। 20 दिन के भीतर ही दिल्ली की जनता को गुमराह किया गया। सादगी का वादा, विलासिता में बदल गया। मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कोविड काल के दौरान जनता की पीड़ा और इस निर्माण के बीच स्पष्ट अंतर बताया। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे, अस्पतालों के चक्कर लगा रहे थे, तब मुख्यमंत्री की महल की एक ही फाइल अति आवश्यक' थी। उन्होंने बताया कि 11 वर्षों में पानी, सीवर, प्रदूषण या कोविड से जुड़ी किसी भी फाइल को यह प्राथमिकता नहीं दी गई।

उन्होंने कहा कि न ऑक्सीजन के लिए, न आईसीयू के लिए, न जान बचाने के लिए—सिर्फ महल के लिए अति आवश्यक' लिखा गया। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कोविड के लिए 787.91 करोड़ रुपये दिए गए, लेकिन उसका पूरा उपयोग नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जान बचाने के लिए मिला पैसा पूरा खर्च नहीं हुआ, लेकिन एक बंगले की लागत 7 करोड़ से बढ़कर 58 करोड़ हो गई। मंत्री प्रवेश साहिब ने आज सदन में एक लंबी प्रिंटिंग पेपर रोल सदन में दिखाई, जिसमें खर्चों की पूरी सूची थी, जैसे-जैसे वह रोल खुलती गई, वैसे-वैसे खर्चों का दायरा सामने आता गया।

संक्षिप्त खबरें

धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत

नई दिल्ली। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईसाई धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति (एससी) की सुविधाएं न मिलने के फैसले का स्वागत किया है। कमेटी का कहना है कि इस निर्णय से विशेषकर पंजाब में धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर रोक लगने की उम्मीद है। मीडिया से बातचीत में कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने कहा कि अदालत का यह फैसला स्पष्ट करता है कि एससी वर्ग की सुविधाएं केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों को ही मिलेंगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है, तो वह इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और इस मुद्दे को कमेटी कई बार उठा चुकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि लगभग 2000 लोगों की सिख धर्म में वापसी भी करवाई गई है। कमेटी ने उम्मीद जताई कि इस फैसले के बाद धर्म परिवर्तन की गतिविधियों में कमी आएगी और लोग समझेंगे कि धर्म बदलने पर उन्हें एससी वर्ग से मिलने वाली आरक्षण और अन्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा।

टैक्स नहीं देने पर संपत्ति सील कर रहा निगम

नई दिल्ली। नगर निगम ने रोहिणी जोन में संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने पर कई व्यावसायिक संपत्तियों को सील किया है। संपत्ति कर विभाग के संयुक्त निर्धारक एवं संग्राहक पंकज सरोहा ने बताया कि मार्च में कई व्यावसायिक संपत्तियों को बकाया कर का भुगतान न करने पर सील किया गया है। कार्रवाई के दौरान अब तक 30 लाख रुपये से अधिक का बकाया भी वसूला गया है। निगम प्रशासन के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान सूरज पार्क के पास एक, शाहबाद डेयरी में तीन, नांगलोई-मुंडका व नीलोठी में चार, बुध विहार, फेज-2 और रिठाला में एक-एक व्यावसायिक संपत्तियों को सील किया गया है।

निगम के स्कूलों में सुधरेगी खेल व्यवस्था

नई दिल्ली। नगर निगम ने अपने प्राथमिक स्कूलों के कायाकल्प की योजना बनाई है। इसके तहत स्कूलों में आधुनिक कंप्यूटर लैब बनाए जाएंगे। साथ ही खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों के मैदानों को सुव्यवस्थित किया जाएगा। बैडमिंटन कोर्ट भी बनाए जाएंगे।

कचरा प्रबंधन-सड़क मरम्मत पर काम की जरूरत : एलजी

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली के उप-राज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने मंगलवार को नगर निगम की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निगम के अफसरों से कचरा प्रबंधन और सड़क मरम्मत जैसे कार्यों पर विशेष ध्यान देने को कहा।

उप-राज्यपाल ने बैठक की तस्वीरें एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि बीते कुछ वर्षों में तमाम बाधाओं के बावजूद निगम ने कई सराहनीय प्रयास किए हैं। इसके बावजूद अभी बहुत कुछ किए जाने की जरुरत है। इनमें कचरा प्रबंधन, सड़कों की मरम्मत, धूल नियंत्रण और नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रमुख है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों कहा कि उन्हें आम लोगों की तरफ से मिलने वाली रचनात्मक प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करना चाहिए। उप-राज्यपाल ने नगर निगम, डीडीए, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण व अन्य विभागों के बीच तालमेल पर भी बल दिया।

गैस सिलिंडर के संकट पर दिल्ली विस के बाहर आप ने किया का प्रदर्शन

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष और आम आदमी पार्टी के नेताओं का सरकार को घेरना जारी है। लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के बाद अब रसोई गैस संकट के विरोध में बुधवार को प्रदर्शन किया गया।

दिल्ली में रसोई गैस सिलिंडर के संकट को लेकर दिल्ली विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष आतिशी के नेतृत्व में पार्टी के विधायक पोस्टर लेकर विधानसभा परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान आप विधायकों ने आरोप लगाया कि दिल्ली में रसोई गैस सिलिंडर का भारी संकट है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को सिलिंडर नहीं मिल पा रहे हैं और लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

यह प्रदर्शन उस समय किया गया जब दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आप विधायकों ने कहा कि सरकार को तुरंत इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए और लोगों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि गैस सिलिंडर की किल्लत से पूरी दिल्ली प्रभावित है। उन्होंने सरकार से मांग की कि गैस आपूर्ति को दुरुस्त किया जाएगा। इस दौरान आप विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।

दिल्ली: करोल बाग में जयपुर से आ रही बस पलटी, दो लोगों की मौत, 23 व्यक्ति घायल

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। मध्य दिल्ली के करोल बाग इलाके में हनुमान मंदिर के पास मंगलवार देर रात एक 'स्लीपर बस' पलटने से दो यात्रियों की मौत हो गई और कम से कम 23 लोग घायल हो गए।

अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि रात करीब एक बजे करोल बाग थाने को घटना की सूचना मिली जिसमें बताया गया कि दुर्घटना के बाद कई यात्री एक बस के अंदर फंसे हुए हैं। मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) रोहित राजबीर ने बताया कि जयपुर से दिल्ली आने वाली बस में लगभग 30 यात्री सवार थे। अधिकारी ने बताया कि करोल बाग थाना प्रभारी (एसएचओ) के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम, पिकेट स्टाफ और रात्रि गश्त कर्मियों के साथ मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर बस को पलटा हुआ पाया। उन्होंने बताया कि यात्री बस के अंदर फंसे थे और मदद के लिए गुहार लगा रहे थे।

डीसीपी ने बताया कि पुलिसकर्मियों, दिल्ली अग्निशमन सेवा और स्थानीय लोगों ने तुरंत फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। उन्होंने कहा कि पास में मौजूद एक जेसीबी मशीन की मदद से बस को सीधा किया गया और फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला गया। निर्मल नामक एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हमारे पहुंचने से लगभग पांच मिनट पहले बस पलट गई और उसमें सवार सभी यात्री घायल हो गए।

वॉल्ड सिटी इलाके में अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 10 गिरफ्तार

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

यह गिरोह पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े नेटवर्क के जरिए अवैध हथियार भारत में सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से एक सब-मशीन गन समेत 21 अत्याधुनिक विदेशी हथियार और 200 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। डीसीपी क्राइम ब्रांच संजीव कुमार यादव के अनुसार यह गिरोह पुरानी दिल्ली के वॉल्ड सिटी इलाके, खासकर जामा मस्जिद क्षेत्र से संचालित हो रहा था। संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाके का फायदा उठाकर आरोपी हथियारों की तस्करी और सप्लाई का काम कर रहे थे। जांच में सामने आया कि आरोपी एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप और वीओआईपी कॉल का इस्तेमाल करते थे और बार-बार सिम कार्ड एवं मोबाइल बदलते थे।

भुगतान हवाला के जरिए किया जाता था। क्राइम ब्रांच की टीम ने इंस्पेक्टर मान सिंह, इंस्पेक्टर अरविंद सिंह और इंस्पेक्टर सुंदर गौतम के नेतृत्व में लगातार तकनीकी निगरानी और मुखबिर तंत्र की मदद से इस पूरे नेटवर्क को ट्रैक किया। 13-14 मार्च को दरियागंज के बृजमोहन चौक के पास जाल बिछाकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में पूरे गिरोह का खुलासा हुआ और अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर बाकी आरोपियों को भी दबोच लिया गया। पुलिस जांच में पता चला कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड शाहबाज अंसारी है, जो फिलहाल भारत से फरार होकर बांग्लादेश में छिपा हुआ है।

वह पहले भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के एक मामले में गिरफ्तार हो चुका है और पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवाला की हत्या से जुड़े नेटवर्क में भी उसका नाम सामने आ चुका है। गिरोह का काम करने का तरीका बेहद संगठित था। पाकिस्तान से हथियार पहले मिडिल ईस्ट भेजे जाते थे, जहां से उन्हें अलग-अलग पार्ट्स में नेपाल पहुंचाया जाता था।

वहां उन्हें दोबारा असेंबल कर भारत-नेपाल सीमा के रास्ते भारत में तस्करी कर लाया जाता था। इसके बाद दिल्ली-एनसीआर समेत अन्य राज्यों में सक्रिय गैंगों को सप्लाई किया जाता था। बरामद हथियारों में चेक रिपब्लिक की बनी स्कॉर्पियन सब-मशीन गन, इटली की बेरेटा, जर्मनी की वाल्थर, ब्राजील की टॉरस और तुर्की की स्टोएगर जैसी अत्याधुनिक पिस्टल शामिल हैं।

विद्यार्थियों के लिए प्रेरक होगा प्रेरणा भवन: प्रो. योगेश सिंह

डीयू कुलपति ने किया स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर का उद्घाटन

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने रामजस कॉलेज के सामने, सामाजिक विज्ञान संकाय परिसर में नए बने प्रेरणा भवन का उद्घाटन डूसू पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया।

यह भवन स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर होगा जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) कार्यालय भी बनाया गया है। औपचारिक उद्घाटन के पश्चात कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने पूरे भवन का अवलोकन किया और कहा कि यह प्रेरणा भवन विद्यार्थियों के लिए प्रेरक होगा। उन्होंने बताया कि यह भवन विभिन्न छात्र केंद्रित गतिविधियों का केंद्र रहेगा। इस अवसर पर कुलपति ने डूसू पदाधिकारियों के साथ चर्चा भी की और स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर के संचालन को लेकर सुझाव भी दिये। कुलपति ने बताया कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस प्रेरणा भवन के ग्राउंड फ्लोर पर 50 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक कैफेटेरिया बनाया गया है और उसके साथ ही एक यूटिलिटी शॉप बनाई गई है।

कैफेटेरिया में स्टोर रूम और किचन की अलग से व्यवस्था की गई है। भवन के बेसमेंट में जिम और गेम जोन बनाया गया है। इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर 120 लोगों की बैठने की क्षमता का एक सेमिनार हाल बनाया गया है। इमारत में सेकंड फ्लोर पर एक मीटिंग रूम और डूसू अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व संयुक्त सचिव के लिए अलग-अलग कार्यालय बनाए गए हैं। इसके साथ ही इस फ्लोर पर पैंट्री और छोटा स्टोर भी रहेगा। प्रेरणा भवन में प्रत्येक तल पर अलग-अलग महिला एवं पुरुष शौचालयों की व्यवस्था भी की गई है।

भवन के थर्ड फ्लोर पर एक आधुनिक सुविधा संपन्न लाइब्रेरी एवं एक रीडिंग हॉल की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर कुलपति प्रो. योगेश सिंह के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर की निदेशक प्रो. रजनी अब्बी, डीयू के वित्त अधिकारी गिरीश रंजन, चीफ इंजीनियर अशोक सैनी, डीन स्टूडेंट्स वेल्फेयर प्रो. रंजन कुमार त्रिपाठी, डूसू के स्टाफ एडवाइजर प्रो. सुरेंद्र कुमार और डूसू अध्यक्ष आर्यन मान व उपाध्यक्ष राहुल झांसला यादव सहित सभी डूसू पदाधिकारी एवं अनेकों शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित रहे।

उत्तर पूर्वी दिल्ली में नाबालिग लड़के का शव मिला

नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में बुधवार तड़के एक पार्क में 17 वर्षीय लड़के का शव मिला। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान जैद के तौर पर हुई है और वह इलाके का ही रहने वाला था। पुलिस को सूचना मिली थी कि पार्क में एक शव है जिसके बाद न्यू उस्मानपुर थाने की एक टीम जग प्रवेश चंद अस्पताल के पास स्थित डीडीए पार्क पहुंची और शव बरामद किया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अपराध और फॉरेंसिक दलों ने मौका-ए-वारदात का मुआयना किया और सबूत जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने पर ही मौत के कारण का पता चलेगा। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

संपादकीय

मौसम की मनमानी

हाल के वर्षों में कम समय के सर्दी के मौसम के बाद तापमान में अचानक वृद्धि, मौसम के पैटर्न में आ रहे असामान्य बदलाव का स्पष्ट संकेत है। सर्दी के बाद वसंत के मौसम का जल्दी चले जाना और जल्दी गर्मी का आना क्षेत्रीय वायुमंडल परिवर्तनों और दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन का कारण माना जा रहा है। जाहिर है मौसम के मिजाज में आ रहे इस असामान्य बदलाव का हमारे जीवन और आजीविका पर गहरा प्रभाव आने वाले दिनों में नजर आएगा, जिसको लेकर देशव्यापी चर्चा जारी है। खासकर उत्तर भारत के कृषि क्षेत्र में इसके नकारात्मक आर्थिक परिणामों को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। चिंता की बात यह भी है कि हिमाचल प्रदेश के सेब के बागों में, कम होती ठंडक से उत्पादकता में गिरावट देखी जा रही है। दरअसल, मौसमी बदलाव फलों के नाजुक जैविक चक्र को बाधित कर रहा है, जिसके चलते उपज में भारी नुकसान के साथ-साथ गुणवत्ता में गिरावट की आशंका व्यक्त की जा रही है। इससे बचने के लिए अनुकूलन उपायों में जलवायु अनुरूप बागवानी पद्धतियों को अपनाने और दीर्घकाल में सेब पट्टी को ऊंचे क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की जरूरत होगी। आवश्यकता होगी कि हम सूखा-सहिष्णु फसलों को अपनाएं। कम जल के बेहतर उपयोग के प्रयास हों। अब सिर्फ वैकल्पिक फसलों के भरोसे ही नहीं रहा जा सकता, कई मोर्चों पर पहल करने की जरूरत होगी। कुल मिलाकर एक स्पष्ट रणनीति को अपनाकर हम बढ़ती गर्मी के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। निस्संदेह, इसमें दो राय नहीं है कि मार्च के पहले सप्ताह में उच्च तापमान का महसूस होना, आने वाले संकट का स्पष्ट संकेत है। अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में ग्रीष्म ऋतु में आने वाले लू के दिनों की संख्या 1980 के बाद से दुगनी से भी अधिक हो गई है। हमारे देश में तीव्र शहरीकरण, सघन निर्माण और हरित क्षेत्रों के लगातार जारी क्षरण के चलते भी तापमान में वृद्धि हुई है। ऐसे में बढ़ते तापमान से उत्पन्न जल व ऊर्जा संकट से निपटने के लिए तत्काल कारगर योजनाओं की जरूरत है। इसके साथ ही शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु में तेजी से होने वाले परिवर्तन के इस नये असामान्य परिदृश्य के लिए नागरिकों की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के लिए भी एक नया चार्टर बनाने की आवश्यकता होगी। सरकारों की तैयारियों को लेकर भी स्पष्ट रीति-नीति का निर्धारण जरूरी है। निस्संदेह, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के निस्तारण के लिए रणनीतियों को लेकर सहभागी दृष्टिकोण प्रभावकारी हो सकता है। आने वाले समय में मौसम की चरम स्थितियां घातक साबित हो सकती हैं, जिनका मुकाबला मौजूदा अपर्याप्त प्रशासनिक योजनाओं के जरिये संभव न होगा। इसके लिए कारगर रणनीतियां बनाने की जरूरत होगी।

निजी स्कूलों की महंगी फीस, बड़े दावे और हकीकत

आज का अभिभावक पहले से कहीं अधिक जागरूक है, लेकिन साथ ही वह अपने बच्चों के भविष्य को लेकर उतना ही चिंतित भी है। वह चाहता है कि उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, बेहतर सुविधाएं प्राप्त करे और जीवन में आगे बढ़े। इसी सोच के चलते वह अक्सर अपनी आय से अधिक खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाता है। कई परिवार ऐसे हैं जो अपनी जरूरतों में कटौती करके, कर्ज लेकर या अतिरिक्त काम करके बच्चों की फीस भरते हैं। उनके मन में यह विश्वास होता है कि महंगे स्कूल में पढ़ाई का मतलब है बेहतर शिक्षा और निश्चित सफलता। निजी स्कूल इसी मनोविज्ञान को समझते हैं और अपने प्रचार में इसका भरपूर उपयोग करते हैं। वे अपने कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम, एयर-कंडीशंड सुविधाओं, खेल गतिविधियों और अन्य आधुनिक संसाधनों को प्रमुखता से दिखाते हैं। इसके साथ ही, वे प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून और रक्षा सेवाओं में सफलता के बड़े-बड़े दावे भी करते हैं। कई बार विज्ञापनों में कुछ चुनिंदा छात्रों की उपलब्धियों को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है, जैसे वह पूरे स्कूल के स्तर को दर्शाती हों।

-डॉ. सत्यवान सौरभ-

आज के दौर में शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं रह गई है, बल्कि यह एक तेजी से बढ़ता हुआ व्यवसाय भी बन चुकी है। शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, निजी स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनके साथ-साथ बढ़ रही है उनके प्रचार-प्रसार की रणनीतियाँ। अखबारों, होर्डिंग्स, सोशल मीडिया और यहां तक कि स्थानीय कार्यक्रमों में भी स्कूलों के आकर्षक विज्ञापन देखने को मिलते हैं। हर स्कूल अपने आप को "सर्वश्रेष्ठ", "भविष्य निर्माता" और "सफलता की गारंटी" देने वाला संस्थान बताता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये दावे वास्तविकता से मेल खाते हैं, या फिर यह केवल अभिभावकों की उम्मीदों और भावनाओं का लाभ उठाने का एक तरीका है?

आज का अभिभावक पहले से कहीं अधिक जागरूक है, लेकिन साथ ही वह अपने बच्चों के भविष्य को लेकर उतना ही चिंतित भी है। वह चाहता है कि उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, बेहतर सुविधाएं प्राप्त करे और जीवन में आगे बढ़े। इसी सोच के चलते वह अक्सर अपनी आय से अधिक खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाता है। कई परिवार ऐसे हैं जो अपनी जरूरतों में कटौती करके, कर्ज लेकर या अतिरिक्त काम करके बच्चों की फीस भरते हैं। उनके मन में यह विश्वास होता है कि महंगे स्कूल में पढ़ाई का मतलब है बेहतर शिक्षा और निश्चित सफलता।

निजी स्कूल इसी मनोविज्ञान को समझते हैं और अपने प्रचार में इसका भरपूर उपयोग करते हैं। वे अपने कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम, एयर-कंडीशंड सुविधाओं, खेल गतिविधियों और अन्य आधुनिक संसाधनों को प्रमुखता से दिखाते हैं। इसके साथ ही, वे प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून और रक्षा सेवाओं में सफलता के बड़े-बड़े दावे भी करते हैं। कई बार विज्ञापनों में कुछ चुनिंदा छात्रों की उपलब्धियों को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है, जैसे वह पूरे स्कूल के स्तर को दर्शाती हों।

लेकिन जब हम इन दावों को गहराई से परखते हैं, तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। वास्तविकता यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का प्रतिशत बहुत कम होता है। चाहे वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा हो, इंजीनियरिंग की प्रतिष्ठित परीक्षाएं हों, या फिर कानून और रक्षा सेवाओं से जुड़ी परीक्षाएं- इनमें सफल होने वाले छात्रों की संख्या अक्सर सीमित होती है। कई बार तो पूरे साल में गिने-चुने छात्र ही इन परीक्षाओं को पास कर पाते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या स्कूल द्वारा किए गए दावे वास्तविकता के अनुरूप हैं? यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी केवल स्कूल की पढ़ाई के आधार पर संभव नहीं होती। अधिकतर छात्र अलग से कोचिंग संस्थानों का सहारा लेते हैं, जहां उन्हें विशेष रूप से इन परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है। वे अतिरिक्त समय, मेहनत और संसाधन लगाते हैं। ऐसे में यदि कोई स्कूल इन छात्रों की सफलता का पूरा श्रेय अपने ऊपर लेता है, तो यह अभिभावकों को गुमराह करने जैसा हो सकता है।

बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम भी किसी स्कूल की गुणवत्ता को मापने का एक प्रमुख आधार होते हैं। लेकिन यहां भी अक्सर देखा जाता है कि बहुत कम छात्र ही 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर पाते हैं। 95 प्रतिशत से ऊपर अंक लाने वाले छात्रों की संख्या तो और भी कम होती है। यदि कोई स्कूल खुद को क्षेत्र का अग्रणी संस्थान बताता है, तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि उसके परिणाम भी उसी स्तर के हों। लेकिन कई बार यह अपेक्षा पूरी नहीं हो पाती। फीस का मुद्दा इस पूरे विषय का सबसे संवेदनशील पहलू है। निजी स्कूलों की फीस लगातार बढ़ती जा रही है, और कई मामलों में यह मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक क्षमता से बाहर हो जाती है। फीस के अलावा भी कई तरह के अतिरिक्त खर्च होते हैं-जैसे परिवहन शुल्क, यूनिफॉर्म, किताबें, वार्षिक शुल्क, गतिविधि शुल्क आदि। कुल मिलाकर, एक बच्चे की शिक्षा पर होने वाला खर्च काफी अधिक हो जाता है।

यहां यह समझना जरूरी है कि स्कूलों को अपने संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है। अच्छे शिक्षक, आधुनिक सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियां-इन सभी का एक खर्च होता है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब फीस और शिक्षा की गुणवत्ता के बीच संतुलन नहीं होता। यदि स्कूल अत्यधिक फीस ले रहा है, तो उससे यह अपेक्षा करना गलत नहीं है कि वह उसी स्तर की गुणवत्ता भी प्रदान करे।

सरकार ने इस समस्या को देखते हुए कई राज्यों में फीस नियंत्रण के लिए नियम और कानून बनाए हैं। फीस रेगुलेशन कमेटियां गठित की गई हैं, जिनका उद्देश्य स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि को रोकना है। लेकिन व्यवहार में इन नियमों का प्रभाव सीमित दिखाई देता है। कई बार अभिभावकों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती, और वे अकेले आवाज उठाने से हिचकिचाते हैं।

इस स्थिति में अभिभावकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें केवल विज्ञापनों के आधार पर निर्णय लेने के बजाय स्कूल के वास्तविक प्रदर्शन, शिक्षकों की गुणवत्ता, और पिछले परिणामों का गंभीरता से विश्लेषण करना चाहिए। यदि संभव हो, तो अन्य अभिभावकों से बातचीत करनी चाहिए और उनके अनुभव जानने चाहिए। स्कूल के दावों और वास्तविकता के बीच अंतर को समझना आवश्यक है। इसके अलावा, यदि अभिभावकों को लगता है कि स्कूल पारदर्शिता नहीं बरत रहा है या गलत दावे कर रहा है, तो उन्हें सामूहिक रूप से आवाज उठानी चाहिए। एकजुट होकर स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगना, और आवश्यक होने पर संबंधित शिक्षा अधिकारियों या बोर्ड के पास शिकायत दर्ज कराना, एक प्रभावी कदम हो सकता है। इससे न केवल समस्या का समाधान हो सकता है, बल्कि भविष्य में ऐसी स्थितियों को रोका भी जा सकता है।

यह भी जरूरी है कि हम सफलता की परिभाषा को केवल अंकों और प्रतियोगी परीक्षाओं तक सीमित न रखें। हर बच्चा अलग होता है, उसकी रुचियां और क्षमताएं भी अलग होती हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल एक परीक्षा में सफलता दिलाना नहीं, बल्कि बच्चे के समग्र विकास को सुनिश्चित करना होना चाहिए। एक अच्छा स्कूल वही है जो बच्चे को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करे।

आज के समय में यह समझना बेहद जरूरी है कि कोई भी स्कूल सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। स्कूल केवल एक मंच प्रदान करता है, जहां से बच्चा अपनी यात्रा शुरू करता है। उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना मेहनत करता है, उसे कैसा मार्गदर्शन मिलता है, और उसका वातावरण कैसा है।

अंततः, शिक्षा को एक सेवा के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि केवल एक व्यापार के रूप में। स्कूलों की जिम्मेदारी है कि वे पारदर्शिता बनाए रखें, अपने दावों के प्रति जवाबदेह रहें, और अभिभावकों के विश्वास को बनाए रखें। वहीं, अभिभावकों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे जागरूक रहें, सही जानकारी के आधार पर निर्णय लें, और आवश्यकता पड़ने पर अपनी आवाज उठाएं। यदि इन दोनों पक्षों के बीच संतुलन और विश्वास बना रहता है, तभी हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं जो वास्तव में बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बना सके, न कि केवल एक महंगा सौदा बनकर रह जाए।

डिजिटल युग में ठगी के बढ़ते जाल से कैसे मिलेगी निजात

-सौरभ वार्ष्णेय-

देश की राजधानी दिल्ली आज सिर्फ राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र ही नहीं, बल्कि साइबर और वित्तीय अपराधों का भी बड़ा केंद्र दिखाई दे रही है। प्रतिदिन औसतन 50 लाख रुपये की ठगी के मामलों का सामने आना न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि यह कानून-व्यवस्था और डिजिटल सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यह आंकड़े एक दैनिक अखबार में प्रकाशित किये गए हैं जो चौंकाने वाले दिख रहे हैं। वर्ष 2025 में 184 मामले दर्ज किये गए हैं, लगभग 70, 64, 80, 424 रूपये (30 जून तक) तक ठग लिए गये हैं। इससे पिछले वर्ष 2024 में 1, 591 मामले दर्ज हुए और 8, 17, 64, 85, 471 रूपये ठग लिए गए। आज ठगी से कैसे बचे? अभी गैस की क्या कमी हुई ठगों ने इस आपदा को अवसर बना लिया। इस डिजिटल युग में ठगी के बढ़ते जाल से कैसे निजात मिलेगी तो विशेषज्ञों का कहना है कि जागरुकता और सतर्कता सावधानी जरूरी है।

दिल्ली जैसी राजधानी में दिल्ली पुलिस अच्छा कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में तकनीक के विस्तार के साथ ठगी के तरीके भी बेहद परिष्कृत हो गए हैं। पहले जहां जेबकतरी और साधारण धोखाधड़ी आम थी, वहीं अब ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल, अपडेट के नाम पर ठगी, और निवेश के झांसे जैसे अपराध तेजी से बढ़े हैं। आम नागरिक, विशेषकर बुजुर्ग और डिजिटल रूप से कम जागरूक लोग, इन ठगों का आसान शिकार बन रहे हैं। दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियां लगातार जागरूकता अभियान चला रही हैं, लेकिन अपराधियों की चतुराई और तकनीकी दक्षता कई बार इन प्रयासों पर भारी पड़ती है। अपराधी अक्सर विदेशी सर्वर, फर्जी सिम कार्ड और डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छिपा लेते हैं, जिससे जांच और गिरफ्तारी में कठिनाई आती है।

यह स्थिति कई स्तरों पर चिंता पैदा करती है। पहला, आम जनता का डिजिटल लेनदेन पर विश्वास कमजोर होता जा रहा है। दूसरा, देश की आर्थिक सुरक्षा पर इसका असर पड़ता है। तीसरा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता और संसाधनों पर भी प्रश्न उठते हैं। समाधान के लिए बहुस्तरीय रणनीति आवश्यक है। सबसे पहले, साइबर अपराध से निपटने के लिए पुलिस बल को अत्याधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण से लैस करना होगा। दूसरे, बैंकों और डिजिटल पेमेंट कंपनियों को अपनी सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाना होगा। तीसरे, स्कूलों और सामाजिक मंचों के माध्यम से डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि लोग ठगी के नए-नए तरीकों से परिचित हो सकें।

इसके अलावा, सरकार को सख्त कानून और त्वरित न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, ताकि अपराधियों में डर पैदा हो। साथ ही, आम नागरिकों को भी सतर्क रहना होगा- अनजान कॉल, लिंक या ऑफर पर भरोसा करने से पहले पूरी जांच करना जरूरी है।

हाल के महीनों में दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर संयुक्त आयुक्त रजनीश गुप्ता के नेतृत्व में ऑपरेशन साई-हॉक के तहत दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। इस ऑपरेशन का उद्देश्य उन कॉल सेंटरों और गिरोहों को नेस्तनाबूद करना था जो फर्जी केवाईसी, लॉटरी और निवेश के नाम पर लोगों को लूटते हैं। इस कार्रवाई के बाद साइबर अपराधों की दर में गिरावट दर्ज की गई। अब जांच टीम के विस्तार से इस पकड़ को और मजबूत किया जा सकेगा।

यह समझना होगा कि डिजिटल युग में सुरक्षा केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह ठगी का जाल और भी व्यापक रूप ले सकता है, जिससे न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक विश्वास भी प्रभावित होगा।

यह आंकडे तो दिल्ली के है देश भर में यह ठगी का आंकडा बड़ा भी हो सकता है। लेकिन सतर्कता सावधानी जरूरी है।

डिजिटल ठगी से कैसे निजात पाएं

डिजिटल युग ने जहां हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं ठगों के लिए नए रास्ते भी खोल दिए हैं। आज मोबाइल, इंटरनेट और ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते उपयोग के साथ डिजिटल ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हर दिन आम लोग अपनी मेहनत की कमाई साइबर अपराधियों के जाल में फंसा रहे हैं। ऐसे में यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि डिजिटल ठगी से कैसे बचा जाए और इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण कैसे हो। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डिजिटल ठगी केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि जागरूकता की कमी का परिणाम भी है। ठग अक्सर फर्जी कॉल, मैसेज, ईमेल या लिंक के माध्यम से लोगों को भ्रमित करते हैं। आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा, केवाईसी अपडेट करें, लॉटरी लगी है -जैसे लालच और डर पैदा करने वाले संदेश लोगों को जल्दी फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। इसी जल्दबाजी का फायदा अपराधी उठाते हैं। इस समस्या से निजात पाने का पहला और सबसे प्रभावी उपाय है-जागरूकता। आम नागरिकों को यह समझना होगा कि कोई भी बैंक या सरकारी संस्था कभी भी फोन या मैसेज के जरिए पासवर्ड या नहीं मांगती। ऐसे किसी भी अनुरोध को तुरंत नजरअंदाज करना चाहिए। साथ ही, अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचना और केवल आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का ही उपयोग करना जरूरी है।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है-तकनीकी सुरक्षा। मोबाइल और कंप्यूटर में अपडेटेड एंटीवायरस रखना, मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना और समय-समय पर पासवर्ड बदलना जरूरी है। दो-स्तरीय सुरक्षा का उपयोग भी ठगी के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकता है। तीसरा, सरकार और संस्थाओं की भूमिका भी बेहद अहम है। साइबर अपराधों पर सख्त कानून, त्वरित कार्रवाई और पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिलना आवश्यक है। साथ ही, पुलिस और साइबर सेल को आधुनिक तकनीक से लैस करना और उनकी क्षमता बढ़ाना समय की मांग है। जन-जागरूकता अभियान भी लगातार चलाए जाने चाहिए, ताकि ग्रामीण और शहरी-दोनों क्षेत्रों में लोग सतर्क रहें। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति ठगी का शिकार हो जाता है, तो उसे घबराने की बजाय तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। 1930 हेल्पलाइन या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराना चाहिए, ताकि समय रहते पैसे को रोका जा सके।

डिजिटल ठगी से लड़ाई केवल सरकार या पुलिस की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। जब तक हर व्यक्ति सतर्क और जागरूक नहीं होगा, तब तक इस समस्या पर पूरी तरह नियंत्रण संभव नहीं है। डिजिटल सुविधाओं का लाभ उठाते हुए हमें सावधानी और समझदारी भी अपनानी होगी। यही डिजिटल सुरक्षा का मूल मंत्र है और इसी से हम ठगी के इस बढ़ते खतरे से निजात पा सकते हैं।

सूर्य दोष के लक्षण क्या है?

वैदिक ज्योतिष के मुताबिक किसी भी व्यक्ति की कंडली में सूर्य की दशा गहरा प्रभाव डालती है। सूर्य आत्मा, ऊर्जा, आत्मविश्वास और अधिकार का प्रतीक माना जाता है। यह नेतृत्व, प्रसिद्धि और व्यक्तिगत शक्ति से जुड़ा होता है। मान्यता है कि अगर कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में हो, तो करियर में उन्नति और समाज में सम्मान मिलता है। लेकिन अगर सूर्य कमजोर या अशुभ स्थिति में हो, तो जातक को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं कि सूर्य ग्रह दोष के लक्षण क्या है और इसे मबजूत करने के उपाय क्या है। चलिए इसके बारे में जानते हैं।

सूर्य दोष के लक्षण

-मान्यता है कि सूर्य के कुंडली में कमजोर होने पर व्यक्ति में अहंकार आ जाता है।

-आत्मविश्वास की कमी झलकती है।

-इसके साथ ही व्यक्ति की मान सम्मान में कमी आ जाती है।

-इतना ही नहीं व्यक्ति हिंसक प्रवृत्ति का होता है और वह स्वार्थ, क्रोध, ईर्ष्या आदि से भी व्यक्ति ग्रसित हो जाता है।

-सूर्य दोष है, तो जातक को पिता या पितातुल्य लोगों का सहयोग नहीं मिलता है।

-नौकरी में परेशानियां, कानूनी विवाद और सेहत से जुड़ी परेशानियां भी कुंडली में सूर्य के कमजोर होने का लक्षण हैं।

-सूर्य के कमजोर होने पर जातक को शारीरिक और मानसिक कष्ट से गुजरना पड़ता है।

-इसके साथ ही घर पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

कैसे जानें

आप अपनी कुंडली देखकर सूर्य की दुर्बल स्थिति का पता लगा सकते हैं। कुंडली में अगर सूर्य तुला राशि में विराजमान हैं तो वह प्रतिकूल परिणाम देंगे। इसके साथ ही अगर सूर्य कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में किसी नीच ग्रह के साथ हैं तो भी सूर्य कमजोर माने जाते हैं।

सूर्य दोष को दूर करने के उपाय

वैदिक ज्योतिष में सूर्य दोष से बचने के लिए कई उपाय भी बताए गए हैं। चलिए इन कुछ विशेष उपायों के बारे में जानते हैं।

आज का इतिहास

1953 - जोनास साल्क ने पोलियो से बचाव के लिए नए टीके की खोज की घोषणा की।
1971 - शेख मुजीबुर्रहमान ने बांग्लादेश को स्वतंत्र देश घोषित किया।
1972 - तत्कालीन राष्ट्रपति वी वी गिरी ने पहले अंतरराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का उद्घाटन किया।
1973 - लंदन स्टॉक एक्सचेंज में महिलाओं की भर्ती की शुरुआत।
1974 - लाता गांव, हेन्वाल घाटी, गढ़वाल हिमालय में गौरा देवी के नेतृत्व में 27 महिलाओं के एक समूह ने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों के आसपास घेरा बना लिया और उन्हें अपने इस प्रयास से भारत में चिपको आंदोलन को आरंभ किया।
1975 - जैविक हथियार संधि अस्तित्व में आई।
1979 - अमेरिका में मिस्र-इजराइल समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
1995 - 15 सदस्यीय यूरोपीय यूनियन के सात देशों के बीच आंतरिक सीमा नियंत्रण समाप्त।
1998 - चीन ने अमेरिकी इरीडियम नेटवर्क के दो उपग्रहों को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया।
1999 - द. अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने देश की प्रथम प्रजातांत्रिक संसद के विघटन की घोषणा की।
2001 - केन्या में छात्रावास में आठ लगने से 58 छात्र मरे।
2003 - पाकिस्तान ने 200 कि.मी. की दूरी तक मार करने वाली परमाणु प्रक्षेपास्त्र 'अब्दाली' का परीक्षण किया।
2006 - मेलबर्न में 18वें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन।
2008 - भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कोष में 2.90 करोड़ रुपये की हेराफेरी के मामले में बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया को गिरफ्तार किया गया।
2008 - टाटा मोटर्स ने अमेरिकी कंपनी 'जगुआर' व 'लैंड रोवर' का अधिग्रहण किया।
2008 - युसुफ रजा गिलानी ने पाकिस्तान के 25वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। भारत व पाकिस्तान ने एक-दूसरे के युद्ध बन्दियों को रिहा करने के लिए विदेश मंत्रालय स्तर पर बातचीत शुरू की।
2020 - कोरोना वायरस से दुनियाभर में मरने वालों की संख्या 21 हजार से अधिक हुई। यूरोप में महामारी के मामले 2,50,000 के पार।

बिजली और पानी को पहाड़ों तक पहुंचना है

-दीक्षा-

उत्तराखंड के बागेश्वर जिले का पोलिंग गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसा यहां का जीवन शांत और सरल प्रतीत होता है। लेकिन इस शांति के पीछे यहां समस्याओं का एक बहुत बड़ा अंबार छुपा हुआ है, जो यहां के लोगों, खासकर महिलाओं और किशोरियों के रोजमर्रा के जीवन में साफ दिखाई देती है। पानी और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें यहां अब भी एक संघर्ष बनी हुई हैं, और मौसम बदलते ही यह संघर्ष और भी अधिक कठिन हो जाता है। बारिश और बर्फबारी के दौरान यहां के हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि जीवन की सामान्य गति थम सी जाती है।

जिला बागेश्वर से करीब 25 किमी दूर कपकोट ब्लॉक स्थित पोलिंग गाँव की आबादी लगभग ढाई हजार है। अनुसूचित जाति बहुल इस गाँव में लगभग 350 मकान हैं। लेकिन यहां बिजली और पानी की समस्या वर्षों से बनी हुई है। गांव में पाइपलाइन तो बिछाई गई है, लेकिन यह व्यवस्था स्थायी नहीं है। बरसात के दिनों में भूस्खलन के कारण पाइप लाइन बार-बार टूट जाती है, और सर्दियों में पानी जम जाने से सप्लाई रुक जाती है। ऐसे में गांव की महिलाओं और किशोरियों को कई किलोमीटर दूर पहाड़ी रास्तों से होकर पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। यह रास्ता आसान नहीं होता, बल्कि फिसलन भरा और खतरनाक होता है, जिसमें हर कदम पर गिरने का डर बना रहता है। बिजली की अनियमितता भी पोलिंग गांव की बड़ी समस्या है। यहां बिजली के खंभे और तार तो मौजूद हैं, लेकिन बारिश और बर्फबारी के समय ये अक्सर टूट जाते हैं, जिससे कई दिनों या हफ्तों तक बिजली नहीं रहती। इससे न केवल अंधेरा छा जाता है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, मोबाइल चार्जिंग, और अन्य जरूरी काम भी प्रभावित होते हैं। 32 साल की मीना खमरियाल बताती हैं कि बारिश के दौरान जब हफ्तों बिजली गायब रहती है तब उनकी और उनके बच्चों की समस्या बहुत बढ़ जाती है।

वह कहती हैं कि बिजली न होने की वजह से उनके बच्चे रात में पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, जिसे देख कर उन्हें बहुत तकलीफ होती है। वह कहती हैं कि गाँव में कुछ लोगों ने अपने घरों में सोलर लाइट की व्यवस्था कर रखी है, जिससे उनका जीवन काफी आसान हो गया है। लेकिन वह आर्थिक रूप से इतनी सक्षम नहीं हैं कि अपने घर में सोलर लाइट की व्यवस्था कर सकें। मीना कहती हैं कि सरकार को गाँव गाँव में लोगों को मुफ़्त सोलर लाइट उपलब्ध करानी चाहिए।

अगर हम पूरे उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो सरकार की नल जल योजना के तहत हर घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, राज्य के लगभग 75 से 80 प्रतिशत ग्रामीण घरों तक नल कनेक्शन पहुंच चुका है, लेकिन पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में यह व्यवस्था पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाई है। पोलिंग गांव इसका एक उदाहरण है, जहां कनेक्शन तो हैं, लेकिन नियमित जल आपूर्ति अभी भी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। वहीं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। वर्ष 2023–2024 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य में इस योजना के अंतर्गत लगभग 2.5 लाख से अधिक घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। इसके साथ ही उत्तराखंड ने लगभग पूर्ण घरेलू विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिसका अर्थ है कि कागजों पर अब लगभग हर घर तक बिजली का कनेक्शन मौजूद है। यह उपलब्धि निश्चित रूप से एक बड़ी प्रशासनिक सफलता के रूप में देखी जाती है, क्योंकि इससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को भी बिजली नेटवर्क से जोड़ा जा सका है।

हालांकि, यदि बागेश्वर जैसे पहाड़ी जिलों की वास्तविक स्थिति पर नज़र डाली जाए, तो तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है। यहां अधिकांश घरों तक बिजली के कनेक्शन तो पहुंच चुके हैं, लेकिन बिजली की आपूर्ति अब भी अनियमित बनी हुई है। विशेषकर बारिश और बर्फबारी के दौरान बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे कई गांवों में घंटों नहीं बल्कि दिनों और कभी-कभी हफ्तों तक बिजली नहीं रहती। इस तरह, कनेक्शन होने के बावजूद लगातार और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति का अभाव ग्रामीण जीवन को प्रभावित करता है। यह स्थिति इस बात को स्पष्ट करती है कि केवल बिजली पहुंचाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भौगोलिक परिस्थितियां पहले से ही चुनौतीपूर्ण हैं। दरअसल विकास केवल योजनाओं और आंकड़ों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका असर जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन में दिखाई देना चाहिए। जब तक हर घर में साफ पानी और हर कमरे में रोशनी नहीं पहुंचेगी, तब तक प्रगति अधूरी रहेगी। इन पहाड़ों के बीच रहने वाली लड़कियां और महिलाएं हर दिन अपने संघर्ष से एक नई उम्मीद को जन्म दे रही हैं। अब समय है कि उनकी इस आवाज को सुना जाए और उनके जीवन में वास्तविक बदलाव लाया जाए, ताकि पहाड़ों का यह संघर्ष एक दिन खुशियों की गूंज में बदल सके और विकास की वास्तविक परिभाषा जमीन पर उतरती नजर आए।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक आदित्य वशिष्ठ द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस, बी-42 सेक्टर -7 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301 से मुद्रित व बी-142/2, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 से प्रकाशित।
संपादकीय एवं संपर्क कार्यालय ए-152 सेक्टर-63, नोएडा-201301 **संपादक - आदित्य वशिष्ठ** कानूनी सलाहकार-पवित्र मोहन शर्मा आर.एन.आई. DELHIN/2012/42452
इस अंक में प्रकाशित सभी समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी होंगे। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे। e-mail: Jbttimes2021@ gmail. Com

वैश्विक संकट के बीच कृषि मंत्री की बैठक

फार्मर आईडी' प्रोजेक्ट को तेजी से लागू करने के दिए निर्देश

नई दिल्ली। वैश्विक अस्थिरता के बीच केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने बुधवार को अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें किसानों के हितों की सुरक्षा और आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का फोकस इस बात पर है कि देश में खाद, बीज और अन्य कृषि संसाधनों की उपलब्धता बनी रहे और किसानों को समय पर सभी सुविधाएं मिलती रहें। कृषि मंत्री ने उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने 'फार्मर आईडी' प्रोजेक्ट को तेजी से लागू करने पर विशेष जोर दिया, ताकि वितरण प्रणाली पारदर्शी बने और सही लाभ सही किसान तक पहुंचे। इस दिशा में जल्द ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों के साथ समन्वय बैठक भी की जाएगी। बैठक में साफ किया गया कि वैश्विक संकट का फायदा उठाकर खाद और बीज की कालाबाजारी या जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्यों को भी निर्देश दिए जाएंगे कि वे निगरानी बढ़ाएं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें। कृषि मंत्री ने बीज उत्पादन से जुड़े पहलुओं की समीक्षा करते हुए बीज सुखाने के लिए आवश्यक गैस और एग्रो-केमिकल्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा दूध और अन्य कृषि उत्पादों के लिए पैकेजिंग सामग्री की कमी न हो, इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय और संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय बनाने पर जोर दिया गया। कृषि क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर रखने के लिए एक विशेष सेल का गठन किया गया है। यह सेल खाद, बीज और कीटनाशकों की उपलब्धता पर साप्ताहिक रिपोर्ट सीधे कृषि मंत्री को सौंपेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत निर्णय लिए जा सकें। बैठक में शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार किसानों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वैश्विक संकट के बावजूद देश में कृषि उत्पादन और आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ने दिया जाएगा।

भारत 6जी तकनीक में करेगा वैश्विक नेतृत्व: सिंधिया

नई दिल्ली। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत 3जी के दौर में पीछे था, 4जी में विश्व के साथ चला, 5जी में आगे बढ़ा और अब 6जी में विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि देश अब 6जी तकनीक में वैश्विक नेतृत्व करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

सिंधिया ने बुधवार को लोकसभा में भाजपा सदस्य बिद्युत वरण महतो के एक सवाल पर कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में स्थापित भारत 6जी एलायंस का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। इससे जुड़े संस्थानों की संख्या 14 से बढ़कर 85 तक पहुंच चुकी है। भारत 6जी के क्षेत्र में विश्व के लगभग 10 प्रतिशत पेटेंट में योगदान करेगा, जिनमें से 4000 पेटेंट पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। भारत का सर्वव्यापी संपर्क प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय मंचों 3जीपीपी और आईटीयू में स्वीकृत हो चुका है। उन्होंने कहा कि भारत 6जी एलायंस के अंतर्गत सात कार्य समूह सक्रिय हैं, जो स्पेक्ट्रम, उपकरण प्रौद्योगिकी, पुर्जे, हरित एवं स्थायित्व, जनसंपर्क और 6जी उपयोग मामलों जैसे क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं। इनकी प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है ताकि समयबद्ध और प्रभावी विकास सुनिश्चित हो सके। सिंधिया ने अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) के बारे में बताया कि इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में फरवरी 2024 में बनाया गया।

इसका उद्देश्य देश में अनुसंधान और नवाचार को नई गति देना है। वर्ष 2023 से 2028 की अवधि के लिए 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें वित्त मंत्री द्वारा 14,000 करोड़ रुपये का बजट घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि एएनआरएफ के तहत आठ प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें उन्नत अनुसंधान अनुदान, प्रधानमंत्री प्रारंभिक करियर अनुसंधान अनुदान, समावेशिता अनुसंधान अनुदान, उत्कृष्टता केंद्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र, नवाचार संकेतक और विश्लेषण, तीव्र नवाचार एवं अनुसंधान साझेदारी और एएनआरएफ अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र शामिल हैं।

इसके अलावा उत्कृष्टता केंद्रों, नवाचार केंद्रों, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग और फैलोशिप कार्यक्रमों के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल 6जी तकनीक में वैश्विक नेतृत्व स्थापित करेगा बल्कि अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भी नई मिसाल कायम करेगा।

सरकार से शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, डिजिटल संप्रभुता पर ठोस नीतिगत कदम उठाने की मांग

नई दिल्ली। राज्यसभा में बुधवार को शून्यकाल के दौरान शिक्षा व्यवस्था, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण संबंधी जानकारी और डिजिटल संप्रभुता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सदस्यों ने सरकार से इन मुद्दों पर ठोस नीतिगत कदम उठाने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि आज की प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली में अंकों की होड़ के कारण पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।

परिवार, स्कूल और समाज के दबाव के चलते बच्चे अत्यधिक तनाव में हैं और कोचिंग पर निर्भर हो रहे हैं। उन्होंने एक अध्ययन का हवाला देते हुए बताया कि देश में बड़ी संख्या में बच्चे तनाव, चिंता, भावनात्मक असंतुलन और अवसाद जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव पर चिंता जताते हुए प्रत्येक 100 छात्रों पर एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक की नियुक्ति की मांग की। साथ ही शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान का प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। कांग्रेस सदस्य रंजीता रंजन ने देश में बढ़ते स्वास्थ्य संकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत में मधुमेह और मोटापे के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर स्पष्ट और सरल पोषण संबंधी जानकारी के अभाव को गंभीर समस्या बताते हुए उन्होंने पैकेट के सामने रंग-आधारित चेतावनी प्रणाली लागू करने की मांग की। इससे खाद्य कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी और लोगों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव होगा। कांग्रेस सदस्य नीरज डांगी ने डिजिटल संप्रभुता का मुद्दा उठाते हुए भारत में स्वदेशी सर्च इंजन विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि चीन, रूस, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, चेक रिपब्लिक और वियतनाम समेत कई देशों का अपना स्वदेशी सर्च इंजन है। इन देशों ने स्वदेशी सर्च इंजन को विकसित कर अपनी डिजिटल संप्रभुता को मजबूत किया है।

अटल आदर्श विद्यालय बंद नहीं किए, सरकार अधूरे काम कर रही पूरे : सीएम सुक्खू

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने अटल आदर्श विद्यालयों को बंद नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्व सरकार के समय शुरू किया गया था और जो काम अधूरा रह गया था, उसे वर्तमान सरकार पूरा कर रही है। उन्होंने यह जानकारी विधायक अनुराधा राणा के सवाल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुपूरक सवाल के जवाब में दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों का पूरा सम्मान करती है। उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रदेश में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अटल आदर्श विद्यालय आवासीय स्कूल हैं, जबकि राजीव गांधी के नाम से बनाए जा रहे स्कूलों में डे बोर्डिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे विद्यार्थियों को दिन के समय पढ़ाई और अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे पहले मूल सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि जिला लाहौल-स्पीति में तीन राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से ऐसे स्कूलों की स्थापना कर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।

केंद्र का को-ऑपरेटिव डिविडेंड इनकम पर बड़ा ऐलान, तीन साल तक मिलेगी टैक्स छूट

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को को-ऑपरेटिव डिविडेंड इनकम पर बड़ा ऐलान किया गया। अब नेशनल को-ऑपरेटिव फेडरेशन से आने वाली डिविडेंड आय पर तीन साल की टैक्स छूट मिलेगी। इस कदम का उद्देश्य देश के छोटे को-ऑपरेटिव को मजबूत करना है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि इस टैक्स छूट का उद्देश्य को-ऑपरेटिव में कम हिस्सेदारी वाले सदस्यों को प्रोत्साहन देना है, जिससे अधिक संख्या में लोग को-ऑपरेटिव से जुड़े। वित्त मंत्री ने कहा कि को-ऑपरेटिव, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) और किसान मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। फाइनेंस बिल पर चर्चा के दौरान बोलते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि समावेशी विकास के लिए लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), किसानों और को-ऑपरेटिव को सशक्त बनाना आवश्यक है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ये क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में रोजगार सृजन में सहायक हैं। वित्त मंत्री ने फाइनेंस बिल में डेटा सेंटर सेवाओं से संबंधित एक नए प्रावधान के बारे में भी बताया।

वित्त मंत्री के मुताबिक, सेफ हार्बर नियम के तहत, संबंधित विदेशी संस्थाओं को ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाली भारतीय कंपनियों को लागत पर 15 प्रतिशत का मार्जिन मिलेगा। सीतारमण ने कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत में परिचालन वास्तविक और लाभदायक बना रहे, साथ ही वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि के बिना फर्जी संस्थाओं के निर्माण को रोका जा सकेगा। सरकारी वित्त को लेकर उठ रही चिंताओं को दूर करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ मामलों में केंद्र ने उपकर और अधिभार के रूप में एकत्र की गई राशि से अधिक खर्च किया है, जो दर्शाता है कि निधियों का उपयोग जन कल्याण के लिए किया जा रहा है। वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे घोषणा की कि तकनीकी चूक के लिए लगने वाले जुर्माने को अब निश्चित शुल्क में परिवर्तित कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इस कदम से व्यवसायों के लिए अनिश्चितता कम होने और अनुपालन आसान होने की उम्मीद है।

एक अन्य उपाय के रूप में, सरकार ने हवाई अड्डों पर विवादों को कम करने और यात्रियों के लिए प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए यात्री भत्तों को युक्तिसंगत बनाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों को मजबूत करना, व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक विकास से समाज के व्यापक वर्ग को लाभ मिले।

कुंभ मेला 2027: पुलिस और अग्निशमन कर्मियों के लिए बनेंगी आधुनिक बैरकें

हरिद्वार। कुंभ मेला-2027 की ड्यूटी के दौरान तैनात सुरक्षा कर्मियों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त बैरकों के निर्माण की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है।

रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन में महिला पुलिसकर्मियों के लिए 100 बेड क्षमता की बैरक का निर्माण कराया जा रहा है। यह बैरक महिला कर्मियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की जा रही है। ऋषिकेश स्थित भद्रकाली पुलिस चौकी में भी पुलिसकर्मियों के लिए बैरक निर्माण का कार्य किया जा रहा है। कुंभ मेला व्यवस्थाओं के तहत हरिद्वार में पुलिसकर्मियों के लिए 300 बेड क्षमता की एक बड़ी बैरक के निर्माण का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। इसके साथ ही अग्निशमन कर्मियों के लिए अलग से बैरकों के निर्माण की योजना बनाई जा रही है, ताकि आपातकालीन सेवाओं में तैनात कर्मचारियों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सके। इसी क्रम में मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका के निर्देश पर अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती ने संबंधित अधिकारियों की टीम के साथ बैरागी कैंप स्थित घोड़ा पुलिस लाइन तथा मायापुर स्थित फायर स्टेशन परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बैरकों के निर्माण के लिए उपलब्ध भूमि, पहुंच मार्ग, यातायात की सुगमता और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का गहन अध्ययन किया। अपर मेलाधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित स्थलों के संबंध में रिपोर्ट मेलाधिकारी को प्रस्तुत कर अंतिम स्वीकृति के लिए शासन को भेजी जाएगी, ताकि निर्माण कार्य समय से पूरा कराया जा सके।

मप्र में पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाह के बाद पंपों पर उमड़ी भीड़, खाद्य मंत्री बोले- स्टॉक की कमी नहीं

भोपाल। मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया पर पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाह फैलने के बाद प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। बुधवार को भी सुबह से कई जगहों पर लम्बी कतारें लगी हुई हैं और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।

इंदौर, भोपाल, शाजापुर, खरगोन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, आगरमालवा, धार, खंडवा, नीमच आदि जिलों में भी सुबह से कई पेट्रोल पम्पों पर भीड़ देखी जा रही है। हालांकि, प्रशासन और पेट्रोल पंप संचालकों का साफ कहना है कि कहीं भी ईंधन की कमी नहीं है। पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सप्लाई भी लगातार जारी है। इसके बावजूद लोग पैनिक में टैंक फुल करवा रहे हैं, जिससे कुछ जगहों पर अव्यवस्था की स्थिति बन गई।

मध्य प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बुधवार को बयान जारी कर कहा है कि मंगलवार (24 मार्च) को प्रदेश के कुछ जिलो में पेट्रोल पंपों पर आम जनता के बीच अफवाह की स्थिति के कारण लाइनें लगने तथा उपभोक्ताओं द्वारा पेट्रोल की पैनिक खरीद का मामला संज्ञान में आया। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल एवं डीजल के स्टॉक की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल, डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डिपो से भी पेट्रोल पंपों को निरंतर आपूर्ति की जा रही है। किसी भी प्रकार की अफवाह से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। घबराहट में न तो खरीदारी करें और न ही किसी प्रकार का संग्रह करें। मंत्री राजपूत के अनुसार, ऑयल कंपनियों द्वारा अवगत कराया गया है कि आज की स्थिति में प्रदेश में पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। वर्तमान में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हो रही है।

पीएनजी और सीएनजी आपूर्ति पर जोर, भारत के पास ईंधन का पर्याप्त भंडार : पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच सरकार ने बुधवार को देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति स्थिति को सामान्य बताया है। भारत के पास ईंधन का पर्याप्त भंडार है। रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और लगभग 26 करोड़ टन तेल उपलब्ध है।

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 25 दिनों में 2.5 लाख नए पीएनजी कनेक्शन दिए गए, जबकि 2.2 लाख उपभोक्ता एलपीजी से पीएनजी पर चले गए और 2.5 लाख नए आवेदन प्राप्त हुए। शर्मा ने कहा कि एलपीजी की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। इसमें कोई कमी नहीं आई है, जबकि 92 फीसदी से ज्यादा बुकिंग ऑनलाइन हो रही है और बुकिंग का स्तर बढ़ने के बावजूद डिलीवरी सामान्य रूप से हो रही है। उन्होंने बताया कि व्यावसायिक एलपीजी का आवंटन 50 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें होटल, ढाबे, सामुदायिक रसोई और प्रवासी श्रमिकों जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।

इसके तहत लगभग 22 हजार टन एलपीजी की आपूर्ति की गई है और 30 हजार छोटे सिलेंडर बांटे गए हैं। कई राज्यों में वैकल्पिक ईंधन के तौर पर अतिरिक्त केरोसिन (मिट्टी का तेल) का आवंटन भी किया गया है। उन्होंने बताया कि इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली सीएनजी भी 100 फीसदी कंज्यूमर्स को उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि कई कंपनियों ने कई इंसेंटिव्स की घोषणा की है, जैसे 500 रुपये तक की फ्री गैस या सिक्योरिटी डिपॉजिट में छूट दी गई है।

सुजाता शर्मा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसके तहत लगभग 2,700 जगहों पर छापे मारे गए हैं, जबकि 2,000 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों से अपील कर रही है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें और घबराएं नहीं। सरकार उन्हें पर्याप्त आपूर्ति का आश्वासन दे रही है। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकारों को भी लिखा गया है, उन्हें 10 फीसदी कमर्शियल गैस और अतिरिक्त एलपीजी देने का ऑफर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में ही एक ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें रोड रेस्टोरेशन चार्ज माफ कर दिया गया है और 24X7 पाइपलाइन के काम की इजाजत दी गई है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने बताया कि बुधवार को भारत सरकार ने पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक और गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इसका मुख्य मकसद सभी राज्यों में पीएनजी कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन फीस और अप्रूवल टाइमलाइन को आसान बनाना है।

सुजाता शर्मा ने कहा कि हमारे पास हर साल लगभग 26 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफाइन करने की क्षमता है। पिछले दो दिनों में हमने कई इलाकों में रिटेल आउटलेट्स और पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लाइनें देखी हैं और लोग घबराकर भी खरीदारी करते दिखे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसी भी पेट्रोल पंप पर कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंपों को सप्लाई करने वाले टर्मिनलों पर भी पर्याप्त मात्रा में तेल मौजूद है। इसलिए अफ़वाहों पर ध्यान न दें और घबराकर खरीदारी करने से बचें।

जदयू सांसद गिरिधारी यादव की सदस्यता पर संकट, लोस अध्यक्ष से की गई कार्रवाई की मांग

पटना। बिहार के बांका लोकसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के सांसद गिरिधारी यादव की लोकसभा सदस्यता पर संकट गहराता नजर आ रहा है। जदयू ने उनकी सदस्यता समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्टी के संसदीय नेता और सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामत ने लोकसभा अध्यक्ष को आवेदन देकर गिरिधारी यादव की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। पार्टी इसे अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया सख्त कदम बता रही है।

दिलेश्वर कामत ने कहा कि गिरिधारी यादव ने पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान दिया था। इसके अलावा, उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपने बेटे के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से टिकट दिलाया और उसके पक्ष में प्रचार भी किया, जो पार्टी विरोधी गतिविधि मानी गई है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने कहा कि आवेदन संसदीय नेता की ओर से दिया गया है और अब इस पर पार्टी नेतृत्व तथा अध्यक्ष विचार करेंगे।

उन्होंने भी आरोप दोहराया कि गिरिधारी यादव ने अपने बेटे के लिए राजद के टिकट पर चुनाव लड़वाया और खुद प्रचार में सक्रिय रहे।

उत्तर रेलवे
खुली निविदा सूचना
भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल इंजीनियर–ट्रैक, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली द्वारा निम्न कार्य के लिए ई–टेंडर के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

1.	**कार्य का नाम :** ROK बैलेस्ट डिपो, DEN/Track/DLI के अधीन, रेलवे वैगनों में 65 मिमी गेज की मशीन से क्रश्ड हार्ड स्टोन बैलेस्ट की 43387 घन मीटर मात्रा का आपूर्ति, स्टैकिंग एवं लोडिंग का कार्य, जो कि रेलवे स्पेसिफिकेशन IS/RDSO-GE/0001:2023 (फरवरी 2023) तथा इसके नवीनतम करेक्शन स्लिप के अनुरूप हो। बैलेस्ट केवल निर्दिष्ट स्त्रोतों से ही प्राप्त किया जाएगा, अर्थात् रामकुमारपुरा माइनिंग एरिया, ग्राम रामकुमारपुरा, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू (राजस्थान) या खानक माइनिंग एरिया (HSIIDC के नियंत्रण में) तहसील तोशाम, जिला भिवानी (हरियाणा), (उक्त दर में सभी लीड एवं लिफ्ट, जीएसटी, कर आदि शामिल होंगे तथा किसी भी परिस्थिति में कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा) (निविदा आमंत्रण सूचना-21-25-26-ड्ब्ल्युसी)
2.	**अनुमानित लागत:** रु. 9,41,64,755.48/-
3.	**धरोहर राशि:** रु. 18,83,300
4.	**ई-निविदा भरने का दिनांक और समय & ई-निविदा खुलने का दिनांक और समय:** ई–निविदा भरने का समय शुरू दिनांक 02.04.2026 को 15:00 बजे से निविदा खुलने का समय & ई–निविदा खुलने का दिनांक 16.04.2026 को 15:00 बजे तक।
5.	**निविदा की वेबसाइट जहां निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकता है: www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है।

सं: 128-ड्ब्ल्यु.मं.अधि./सं/निविदा आमंत्रण सूचना-21-25-26-ड्ब्ल्युसी दिनांक: 24.03.2026 996/2026
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

जाति के नाम पर राजनीति करने वालों ने गरीबों का भला नहीं किया: सीएम योगी

बहराइच में 136 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास, शौचालय और आवास के लिए भूमि के पट्टों का वितरण

बहराइच। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को जनपद बहराइच में मुख्यमंत्री आवास, शौचालय और आवास के लिए भूमि के पट्टों के 136 लाभार्थी परिवारों को वितरण किया। उन्होंने कहा कि इन परिवारों को यह सब पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन जाति के नाम पर बाँटने वाले लोगों ने देश की जितनी अपूर्णनीय क्षति आजादी के बाद से लगातार की है, उसका खामियाजा यह देश लगातार भुगता है, लेकिन अब मोदीजी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में कार्य हो रहा है।

योगी आदित्यनाथ आज बहराइच जिले के सेमरहना में भरथापुर के विस्थापित परिवारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन 136 परिवारों के 500 लोगों को पिछली सरकारों ने नजरअंदाज किया, आज उन्हें नया जीवन देने का कार्य हो रहा है। अब कोई भी गरीब, दलित, पिछड़ा या जनजातीय परिवार उपेक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि आज जो लोग पीडीए की बात करते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए क्या ये मुन्नालाल मौर्य उसका हिस्सा नहीं हो सकता था? क्या ये भरतापुर के यादव उसके हिस्से नहीं हो सकते थे? क्या यहां का दलित उसका हिस्सा नहीं हो सकता था? क्या यहां के जनजातीय थारू समुदाय के लोगों को इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए की तरह अगर कार्य पहले करने का प्रयास किया होता तो इन गरीबों और वंचितों को भी सुविधाएं मिलती और इनका पुनर्वास बहुत पहले हो गया होता। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कौडियाला सरयू नदी हादसे के बाद जब गांव की स्थिति देखी, तो यह पाया कि ये लोग जंगल असुरक्षित हालात में रह रहे थे। बाघ, हाथी और तेंदुए का डर, तो दूसरी ओर नदी में मगरमच्छ और सांपों का खतरा था। यहां न सड़क थी, न बिजली और न ही पक्के मकान हैं? उन्होंने प्रशासन को निर्देशित किया कि बन रही इस नयी कॉलोनी का नाम भरतपुर ही रखना सुनिश्चित करें। भरतापुर से अब भरतपुर इसका नाम ही रखना और ग्राम पंचायत भी वही रहे, लेकिन वहां पर इसका नाम भरतपुर रहे क्योंकि राम भगवान राम के जन्मदिन के एक दिन पहले जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे, उस समय अयोध्या का शासन भरतजी संभाल रहे थे। उन्होंने भाई से भाई के बीच प्रेम होने का उदाहरण प्रस्तुत किया था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कहीं माफिया का संकट, कहीं गुंडों का संकट, कहीं दंगाइयों का संकट और प्रदेश के बारे में धारणा ऐसी बनाई गई थी कि यहां विकास नहीं चाहिए। यहां पर तो जाति के नाम पर दंगाइयों को प्रश्रय दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आजकल नवरात्र चल रहे हैं। इस बार 26 और 27 मार्च को रामनवमी का आयोजन भव्यता के साथ होगा। 2017 के पहले सन्नाटा होता था, क्योंकि उपद्रव कहां हो जाए। इसकी लोगों को आशंका होती थी। जो लोग 2017 के पहले राम मंदिर का विरोध करते थे, वहीं लोग दंगाइयों को भी प्रश्रय देते थे और इन्हीं लोगों ने प्रदेश को लूटा, लेकिन इन गरीबों की चिंता उनको नहीं थी।

सत्ता में रहते समय इन नेताओं के मन में गरीबों के लिए उनके मन में कोई संवेदना नहीं थी, यहाँ के भी जो पीड़ित और वंचित यादव थे, मौर्य और कुशवाहा जाति से जुड़े हुए लोग थे, जनजातीय समुदाय और दलित समुदाय से जुड़े हुए लोग थे, इनके बारे में उनकी संवेदना जाग सके, इन तक भी योजना का लाभ पहुँच सके, उन्होंने कभी देखने का प्रयास नहीं किया। इस कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारियों के अलावा स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

नवरात्रि की सप्तमी पर सीएम योगी ने शक्तिपीठ देवीपाटन में की शक्ति की आराधना

बलरामपुर। चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को शक्तिपीठ मंदिर देवीपाटन पहुंचे। उन्होंने मां पाटेश्वरी देवी का विधिवत दर्शन-पूजन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में स्थापित पात्र देवता रतन नाथ योगी के दालिचा पर भी पहुंचकर श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना की।

मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर निर्धारित समय से लगभग एक घंटे विलंब से दोपहर 1:20 बजे मां पाटेश्वरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भवानियापुर (तुलसीपुर) स्थित हेलीपैड पर उतरा। हैलीपेड पर देवीपाटन पीठाधीश्वर मिथलेश नाथ योगी महाराज ने स्वागत किया। वहां से कार द्वारा उनका काफिला सीधे देवीपाटन मंदिर पहुंचा। मुख्यमंत्री ने गर्भगृह में पहुंच मां पाटेश्वरी जी का दर्शन-पूजन किया। पूजन-अर्चना के उपरांत मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में स्थित पात्र देवता रतन नाथ योगी के दालिचा पर पहुंचे और श्रद्धापूर्वक मत्था टेका। इस दौरान पूरे मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और श्रद्धालुओं की आवाजाही को व्यवस्थित रूप से संचालित किया गया।

मुख्यमंत्री करीब दो घंटे तक मंदिर परिसर में रुकेंगे। इसके बाद वह कार द्वारा हेलीपैड पहुंचकर आगे के कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। उल्लेखनीय है कि बीते 15 दिनों में मुख्यमंत्री की यह देवीपाटन मंदिर की दूसरी यात्रा है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं और अधिक सुदृढ़ की गई हैं। नवरात्रि मेले के दौरान मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा गया। मंदिर परिसर में साफ-सफाई, सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा गया है ताकि दूर-दराज से आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस से बाप-बेटे की मौत

कानपुर। जिले में कल्याणपुर थाना क्षेत्र में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान पिता-पुत्र की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने करीब एक घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाकर तीन लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर पड़ताल शुरू कर दी है।

कर्नलगंज इलाके के रहने वाले इरफान ने बताया कि रात में कल्याणपुर के गोवा गार्डन स्थित अपार्टमेंट में अपने ससुर जावेद (45) और साले आबिद (25) के साथ सेप्टिक टैंक साफ करने पहुंचे थे। रात करीब 12 बजे तीनों अंदर गए। पहले राउंड में सफाई करने के बाद तीनों बाहर आ गए। इसके बाद करीब दो बजे दोबारा सफाई करने के लिए टैंक में उतरे। जावेद और आबिद गहराई में चले गए। काफी देर तक उनके बाहर न आने पर अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। एसीपी कल्याणपुर आशुतोष कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौत का कारण सीवर टैंक के अंदर मौजूद जहरीली गैस लग रहा है। फिलहाल दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

2027 में बदलाव का मन बना चुकी है जनता : शिवपाल सिंह यादव

प्रयागराज। भाजपा पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को प्रयागराज में कार्यकर्ताओं से कहा कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में बदलाव के लिए जनता मन बना चुकी है। भाजपा सरकार में किसान बदहाल हैं। नौजवान बेरोजगार हैं और महिलाएं असुरक्षा की भावना में जी रही हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज में भी भय का माहौल है।

समय-समय पर भाजपा नेताओं के विभेदकारी बयानों से समाज में भाईचारे की बजाय कटुता का माहौल बन रहा है। प्रदेश और देश की सत्ता से भाजपा सरकार को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरी एकजुटता के साथ काम करना होगा और बूथ स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूत बनाना होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव के प्रयागराज आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत एवं अभिनन्दन किया। सोरांव हाईवे पर कुरगांव के सामने स्थित एक ढाबे पर जुटे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत से अभिभूत वरिष्ठ समाजवादी नेता शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।

उक्त जानकारी देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्त दान बहादुर मधुर ने बताया कि शिवपाल सिंह यादव विधानसभा फूलपुर क्षेत्र के जगतपुर में एक शिक्षण संस्थान द्वारा देश के शहीदों की विधवाओं के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने आए थे।

योगी सरकार का रामनवमी पर बड़ा निर्णय, 26 व 27 मार्च को अवकाश

लखनफ। योगी सरकार ने बुधवार को राम नवमी त्योहार पर बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने जनभावना के सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश में 26 मार्च के साथ अब 27 मार्च को भी अवकाश घोषित किया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि नवरात्र पर्व पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आस्था के सम्मान में योगी सरकार के इस निर्णय का लोगों ने स्वागत किया है, क्योंकि अब रामनवमी पर लगातार दो दिन का अवकाश दिया गया है। गौरतलब है कि पहले राम नवमी पर्व के मद्देनेजर 26 मार्च को छुट्टी घोषित की गयी थी। अब 27 मार्च को भी अवकाश घोषित कर दिया हे। ऐसा होने से अब श्रद्धालुओं की सुविधा को पूजा अर्चना की सुविधा रहेगी। दरअसल नवमी तिथि दोनो दिन गुरुवार और शुक्रवार को पड़ रही है। दोनों ही दिन लोग पर्व मना रहे हैं। यही वजह है कि मंदिरों में भी दोनों ही दिन भक्तों की भीड़ बढ़ने का अनुमान है। इसे देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।

निर्माणाधीन खंभा गिरने से दो मजदूरों की मौत

बलिया। जिले के मधुबनी गांव में बुधवार को एक निर्माणाधीन पुल के खंभे के लिए सरिया बांधते समय ढांचे के अचानक गिर जाने से उसके नीचे दबकर लखीमपुर खीरी जिले के निवासी दो मजदूरों की मौत हो गई और एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी है।

पुलिस के अनुसार तुर्तीपार पुल के निकट एक नए पुल का निर्माण किया जा रहा है, बुधवार पूर्वाह्न साढ़े दस बजे मजदूर खंभे के निर्माण के लिए सरिया बांध रहे थे कि तभी सरिये का ढांचा गिर गया और पप्पू (30), अमित (29) व जुगल (21) मलबे के नीचे दब गए। थाना प्रभारी संजय शुक्ला ने बताया कि मलबे के नीचे दबे तीनों मजदूरों को जेसीबी मशीन की मदद से बाहर निकालकर तत्काल सीयर इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने पप्पू और अमित को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि दोनों लखीमपुर खीरी जिले के धरहरा थाना क्षेत्र के खैरा पुरवा के रहने वाले थे। पीलीभीत जिले के मधेपुरा थाना क्षेत्र के निवासी जुगल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच जारी है।

सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत

देवरिया। जिले के भटनी क्षेत्र में बुधवार सुबह मोटरसाइकिल और स्कूल बस की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई।

पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना सुबह करीब सात बजे भटनी-नूनखार मार्ग पर गन्ना विकास समिति के सामने हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कूल बस छात्रों को लाने के लिए भटनी से जा रही थी, तभी सामने से आ रही मोटरसाइकिल से उसकी टक्कर हो गई। मृतकों की पहचान रफीउल्ला (23) और अभिषेक यादव (22) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने उन्हें महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

भटनी के थाना प्रभारी (एसएचओ) मृत्युंजय राय ने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच जारी है

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अग्रिम जमानत मिली

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यौन शोषण के मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी को बुधवार को अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा ने अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। इससे पूर्व, अदालत ने अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी और कहा था कि नाबालिगों के कथित यौन उत्पीड़न मामले और झूंसी थाने में दर्ज मामले में अविमुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अदालत ने आदेश सुरक्षित रखते हुए याचिकाकर्ताओं को पुलिस जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। उल्लेखनीय है कि पॉक्सो अदालत के निर्देश पर पुलिस ने झूंसी थाने में अविमुक्तेश्वरानंद और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें कई शिष्यों से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है।

हरीश राणा का अंतिम संस्कार किया गया

गाजियाबाद। भारत में 'निष्क्रिय इच्छा मृत्यु' की अनुमति पाने वाले पहले व्यक्ति 31 वर्षीय हरीश राणा का बुधवार सुबह दक्षिणी दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया और इसी के साथ 13 साल से जारी उनके चिकित्सकीय संघर्ष का अंत हो गया। हरीश के एक पड़ोसी ने फोन के जरिए बताया कि उनकी मां निर्मला देवी ने अपने बेटे को हाथ जोड़कर भावुक विदाई दी जबकि उनके पिता अशोक राणा ने शोक जताने आए लोगों से न रोने का आग्रह करते हुए कहा कि उनका बेटा अब ''एक अच्छी जगह'' पर है और वह एक अच्छा बेटा था।

परिवार के सदस्यों के अलावा, महिलाओं के नेतृत्व वाले आध्यात्मिक संगठन ब्रह्माकुमारीज की प्रतिनिधि भी अंतिम संस्कार में शामिल हुईं और उन्होंने हरीश के लिए प्रार्थना की। राणा परिवार गाजियाबाद की राज एम्पायर सोसाइटी में रहता है। इस सोसाइटी के निवासी भी दाह संस्कार में शामिल होने और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के सदस्य, एम्स के कर्मचारी, हरीश के रिश्तेदार और दोस्तों सहित बड़ी संख्या में लोग अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद रहे। हरीश के शव को एम्बुलेंस में श्मशान घाट लाया गया। लोगों ने हरीश को हाथ जोड़कर अंतिम विदाई दी और कुछ लोगों ने शव को चिता पर रखे जाने से पहले उस पर केसरिया मालाएं चढ़ाईं। हरीश के छोटे भाई आशीष राणा ने अपनी बहन भावना के साथ चिता को मुखाग्नि दी।

ब्रह्माकुमारीज की 'सिस्टर' लवली ने कहा कि अंतिम संस्कार के दौरान ध्यान संबंधी मंत्रोच्चार किया गया। 'सिस्टर' लवली ने कहा, ''परिवार ने हरीश की आंखें दान करने का फैसला किया है।'' परिवार के सदस्यों से बात नहीं हो पाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं हो सकी कि क्या कोई अन्य अंग भी दान किये गये हैं। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में ब्रह्माकुमारीज द्वारा एक भोग और प्रार्थना अनुष्ठान आयोजित किया जाएगा जिसमें वे व्यंजन तैयार किए जाएंगे जो हरीश को पसंद थे। उन्होंने कहा, ''हरीश एक दशक से अधिक समय तक खाना नहीं खा सके। अब आत्मा मुक्त है। प्रतीकात्मक रूप से, हम वह भोजन उपलब्ध कराएंगे जो उनके शरीर को प्रिय था।''

उच्चतम न्यायालय ने 11 मार्च को एक ऐतिहासिक फैसले में हरीश राणा के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी। पंजाब विश्वविद्यालय में बीटेक के छात्र हरीश 2013 में चौथी मंजिल की बालकनी से गिर गए थे और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई थीं। तब से वह कोमा में थे। हरीश का 13 साल से अधिक समय तक कोमा में रहने के बाद एम्स-दिल्ली में मंगलवार को निधन हो गया था।

सामूहिक नकल का मूल्यांकन में खुलासा, मामले की जांच शुरू

प्रयागराज। यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की कापियों का मूल्यांकन चल रहा है। इस दौरान अलीगढ़ के एक मूल्यांकन केन्द्र पर प्रयागराज जिले के एक केन्द्र की कापियों के मूल्यांकन में इण्टर के रसायन विज्ञान और इतिहास की कापियों के मूल्यांकन के दौरान ए कापी में लिखे गये उत्तर को काटकर बी कापी के सही उत्तर की कापियों को नत्थी किया गया है। प्रथमदृष्ट्या कापियों को अलग से लिखकर जोड़ा गया है।

म ूल्यांकन में लगे शिक्षकों ने मामले की जानकारी यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह को दी तो उन्होंने सामूहिक नकल मानते हुए उच्च स्तरीय जांच और कापियों के स्क्रीनिंग का आदेश देते हुए मामले का खुलासा करने वाले मूल्यांकन में लगे शिक्षकों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। अलीगढ़ जिले के नौरंगीलाल इण्टरमीडिएट कालेज के मूल्यांकन केन्द्र पर प्रयागराज करछना के पं. अनंतराम पाण्डेय इण्टरमीडिएट कालेज, लेहारी, बसही के इण्टर के रसायन विज्ञान और इतिहास विषय की कापियों का मूल्यांकन चल रहा है। इस दौरान इन दोनों विषयों के कापियों के ए कापी में जो उत्तर लिखा गया

- ए कापी पर लिखकर काटा गया और बी कापी में सही लिखकर जोड़ा गया
- अलीगढ़ के मूल्यांकन केन्द्र पर खुलासा, टीम को किया जाएगा सम्मानित

था, वह काटकर दूसरी बी कापी में सही-सही लिखा गया था। इस मामले की जानकारी मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों ने यूपी बोर्ड सचिव को लिखित दिया। सचिव भगवती सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है।

सचिव ने यूपी बोर्ड के सभी अपर सचिव और प्रयागराज के डीआईओएस पीएन सिंह को आदेश दिया है कि करछना के सम्बंधित केन्द्र की कापियों का मूल्यांकन कहां-कहां हो रहा है, उसकी स्क्रीनिंग की जाये और परीक्षा केन्द्र पर लगे सीसीटीवी और परीक्षकों की जांच की जाए कि यह गड़बड़ी कहां पर और कैसे हुई है। सचिव ने बताया कि गड़बड़ी का खुलासा करने वाले उप नियंत्रक रवीन्द्र पाल सिंह, उप मुख्य परीक्षक संदीप रूहेला, परीक्षक देवेश गुप्ता, धर्मेंद्र कुमार, क्षेत्रपाल सिंह व अखिलेश कुमार को सम्मानित कियाया जाएगा।

पर्पल डे पर हुई एपिलेप्सी क्लिनिक की शुरुआत

गाजियाबाद। न्यूरोलॉजिकल केयर को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वैशाली, के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज ने आज एक डेडिकेटेड एपिलेप्सी क्लिनिक की शुरुआत की। यह विशेष सेवा एपिलेप्सी से पीड़ित मरीजों को समग्र और मल्टीडिसिप्लिनरी इलाज प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

इस ओपीडी सेवा का उद्घाटन मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वैशाली, के न्यूरोसाइंसेज विभाग के वाइस चेयरमैन - डॉ. संजय सक्सेना और न्यूरोलॉजी विभाग के प्रिंसिपल कंसल्टेंट - डॉ. मधुकर त्रिवेदी, की उपस्थिति में किया गया। न्यूरोसाइंसेज की विशेषज्ञ टीम, जिसमे एपिलेप्सी एक्सपर्ट शामिल हैं, हर गुरुवार सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी, जहां मरीजों को एडवांस्ड डायग्नोस्टिक्स, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल इवैल्यूएशन और पोस्ट-ट्रीटमेंट क्रिटिकल केयर सपोर्ट सहित एक स्ट्रक्चर्ड और इंटीग्रेटेड केयर पाथवे प्रदान किया जाएगा।लॉन्च के अवसर पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वैशाली के न्यूरोसाइंसेज विभाग के वाइस चेयरमैन - डॉ. संजय सक्सेना, ने कहा, "एपिलेप्सी सबसे सामान्य न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में से एक है, लेकिन इसे अब भी काफी गलत समझा जाता है और कई मामलों में इसका सही इलाज नहीं हो पाता। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे सही समय पर पहचान और उचित इलाज के जरिए काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

हालांकि, स्टिग्मा, देरी से डायग्नोसिस और स्पेशलाइज्ड केयर की कमी मरीजों के परिणामों को प्रभावित करती है। इस डेडिकेटेड एपिलेप्सी ओपीडी के माध्यम से हमारा उद्देश्य एक ऐसा पेशेंट-सेंट्रिक प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जहां मरीजों को एक ही जगह पर सटीक जांच, एडवांस्ड ट्रीटमेंट और लगातार फॉलो-अप मिल सके। पर्पल डे के साथ इस पहल को जोड़कर हम एपिलेप्सी से जुड़े मिथकों को दूर करने और जागरूकता बढ़ाने की भी उम्मीद करते हैं।" मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वैशाली के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रिंसिपल कंसल्टेंट - डॉ. मधुकर त्रिवेदी, ने कहा, "खासतौर पर युवा मरीजों में समय पर हस्तक्षेप बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सीजर की गंभीरता कम की जा सकती है और लंबे समय में बेहतर न्यूरोलॉजिकल परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। मेडिकल एविडेंस बताता है कि सही समय पर और उचित इलाज से अधिकांश मरीजों में दौरे को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में बड़ा सुधार आता है। मैक्स हॉस्पिटल, वैशाली, में हमारा फोकस मल्टीडिसिप्लिनरी मॉडल के जरिए पूरी तरह समग्र एपिलेप्सी केयर प्रदान करना है।

एडवांस्ड मेडिकल थेरेपी से लेकर एपिलेप्सी सर्जरी के लिए इवैल्यूएशन और कॉम्प्लेक्स मामलों में क्रिटिकल केयर सपोर्ट तक, हम इस बीमारी के हर पहलू को संभालने में सक्षम हैं।"पर्पल डे (एपिलेप्सी अवेयरनेस डे) से पहले इन विशेष ओपीडी सेवाओं की शुरुआत मैक्स हॉस्पिटल, वैशाली की क्लिनिकल एक्सीलेंस और पेशेंट-सेंट्रिक इनोवेशन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आधुनिक चिकित्सा विशेषज्ञता और जागरूकता अभियानों के संयोजन के माध्यम से अस्पताल का उद्देश्य इलाज की कमी को दूर करना और एपिलेप्सी मरीजों को सम्मानजनक और बेहतर देखभाल उपलब्ध कराना है।

पति ने किया लोहे की छड़ से हमला, पत्नी की मौत

सोनभद्र। जिले में एक व्यक्ति ने पत्नी पर लोहे की छड़ से हमला किया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी हर्ष पांडेय ने बताया कि मंगलवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि बीजपुर थानाक्षेत्र के अंतर्गत महुआबारी गांव में कन्हैया नामक व्यक्ति और उसकी पत्नी सुमन देवी के बीच झगड़ा हुआ और कन्हैया ने गुस्से में सुमन पर कथित रूप से लोहे की छड़ से हमला कर दिया जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस घायल महिला को धन्वंतरि अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि आरोपी जिले के ही म्योरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है तथा अपनी ससुराल में रह रहा था। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा महिला शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

लैक्रॉस टीमों से लॉस एंजेलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रचने का आह्वान

नई दिल्ली। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को भारतीय पुरुष और महिला लैक्रॉस टीमों को रियाद में आयोजित एशियन लैक्रॉस गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से कड़ी मेहनत जारी रखने और लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रचने का लक्ष्य रखने का आह्वान किया।

खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए खेल मंत्री ने कहा कि लैक्रॉस जैसे उभरते खेलों में सफलता के लिए दृढ़ संकल्प, अंतरराष्ट्रीय अनुभव और निरंतर मेहनत बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, "लैक्रॉस भारत के लिए एक उभरता हुआ बड़ा खेल है। यह आपका पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय अनुभव था और आपने पहले ही देश के लिए पदक जीत लिए हैं। अब आपको और मेहनत करनी है, अधिक अनुभव हासिल करना है और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर देश का नाम रोशन करना है।" उन्होंने यह भी कहा कि सरकार खेलो इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से खिलाड़ियों को लगातार समर्थन देती रहेगी, लेकिन सफलता के लिए जुनून और निरंतर प्रयास सबसे महत्वपूर्ण हैं। भारत ने इस साल फरवरी में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित एशियन लैक्रॉस गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिक्सेस फॉर्मेट में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीते।

भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में इराक को हराया, जबकि महिला टीम ने पाकिस्तान को मात दी। गौरतलब है कि भारतीय महिला लैक्रॉस टीम ने 2024 में और पुरुष टीम ने 2025 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण किया था, ऐसे में यह उपलब्धि और भी खास मानी जा रही है। टीमों में देश के विभिन्न राज्यों–राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश–के खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया। भारत की अगली बड़ी प्रतियोगिताएं अप्रैल में चीन के चेंगदू में होने वाले एशियन लैक्रॉस गेम्स और अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली एशिया-पैसिफिक सिक्सेस लैक्रॉस चैंपियनशिप हैं, जो लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक क्वालिफिकेशन का अहम हिस्सा होंगी।

भारतीय तीरंदाजों ने एशिया कप के पहले चरण में दो कांस्य जीते, दो फाइनल में पहुंचे

बैंकॉक। भारतीय तीरंदाजों ने एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट के पहले चरण में बुधवार को दूसरे दिन दो कांस्य पदक जीते जबकि पुरूष रिकर्व और महिला कंपाउंड टीम स्पर्धाओं के फाइनल में भी प्रवेश कर लिया । महिला कंपाउंड टीम ने पिछली बार कांस्य जीता था लेकिन इस बार फाइनल खेलकर पदक का रंग बेहतर करेगी ।

चिकिथा तानीपर्थी, राज कौर और तेजल साल्वे की तिकड़ी ने स्थानीय खिलाड़ी कन्यावी मानीसोम्बात्कुल, कानोकनापुस काएचोम्फू और चानीदप्पा तानारप्तितिनान को 229 . 226 से हराया । अब सेमीफाइनल में उनका सामना तीसरी वरीयता प्राप्त कजाखस्तान से होगा । पुरूष कंपाउंड वर्ग में क्वालीफिकेशन दौर में शीर्ष पर रहने के बावजूद भारतीय तीरंदाज खिताब बरकरार रखने में नाकाम रहे और कांस्य से संतोष करना पड़ा।

रजत चौहान, ऋषभ यादव और उदय कम्बोज को वियतनाम के हाथों सेमीफाइनल में 233 . 234 से पराजय मिली। कांस्य पदक के मुकाबले में भारतीय टीम ने भूटान को 234 . 232 से हराया । रिकर्व वर्ग में भारतीय पुरूष टीम मलेशिया को 5 . 1 से हराकर फाइनल में पहुंच गई । भारत के देवांग गुप्ता, सुखचैन सिंह और जुयेल सरकार ने एक भी सेट गंवाये बिना जीत दर्ज की।

अब उनका सामना कजाखस्तान से होगा। महिला रिकर्व टीम की तिकड़ी रूमा बिस्वास, कीर्ति और रिद्धि फोर ने मलेशिया को 5 . 1 से हराकर कांस्य पदक जीता।

सरकार ने रमण मूर्ति को तीन साल के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया

नई दिल्ली। सरकार ने के वी रमण मूर्ति को तीन साल के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के साथ ही नियामक बोर्ड में अब चारों पूर्णकालिक सदस्यों का पद भर गया है। अन्य तीन पूर्णकालिक सदस्य अमरजीत सिंह, कमलेश चंद्र वार्ष्णेय और संदीप प्रधान हैं। मूर्ति 1991 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आईडीएएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। इससे पहले वह रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्य कर चुके हैं। मंगलवार देर रात जारी एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, मूर्ति की नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) के लिए की गई है।

तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करें पंत : फाफ डु प्लेसी

नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसी का मानना है कि ऋषभ पंत को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिये और उन्होंने यह भी कहा कि जोखिम लेकर खेलने की बजाय उन्हें आगामी आईपीएल में निरंतरता पर फोकस करना चाहिये। पंत ने अपने बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करके पिछले सत्र में चौथे नंबर से सलामी बल्लेबाज के तौर पर और फिर निचले क्रम पर भी बल्लेबाजी की। वह लखनऊ सुपर जाइंट्स के लिये आखिरी मैच में तीसरे नंबर पर 61 गेंद में नाबाद 118 रन की पारी खेल सके। डु प्लेसी ने जियो स्टार के 'आईपीएल टुडे लाइव' कार्यक्रम में कहा कि शायद पंत के लिये तीसरे नंबर पर खेलने का मौका हो। उन्होंने कहा कि लगता है कि वह तीसरे नंबर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं । मैंने पिछले सत्र में उन्हें लखनऊ के लिये तीसरे नंबर पर खेलते देखा जब निकोलस पूरन चौथे नंबर पर उतरे थे। आरसीबी के पूर्व कप्तान ने कहा कि लखनऊ टीम की 2026 की नीलामी को देखें तो उनके पास शीर्षक्रम पर पंत के साथ एडेन मार्क्रम, मिचेल मार्श और पूरन जैसे धुरंधर हैं। पंत को अपना प्रभाव और छोड़ना होगा ।

महिला क्रिकेट: न्यूजीलैंड ने पांचवें टी-20 में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 4-1 से जीती सीरीज

क्राइस्टचर्च। अमेलिया केर के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत न्यूजीलैंड ने बुधवार को पांचवें टी-20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 92 रनों से हराकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। हैगले ओवल में खेले गए इस मुकाबले में केर ने 55 गेंदों पर 105 रनों की तूफानी पारी खेलने के साथ गेंदबाजी में भी दो विकेट झटके। इस शानदार प्रदर्शन के लिए अमेलिया केर को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और इसाबेला गेज जल्दी आउट हो गईं। इसके बाद अमेलिया केर और जॉर्जिया प्लिमर ने पारी को संभालते हुए दूसरे विकेट के लिए 45 रनों की साझेदारी की। हालांकि तुमी सेखुखुने ने लगातार दो गेंदों पर विकेट लेकर न्यूजीलैंड को झटका दिया, लेकिन केर ने आक्रामक अंदाज जारी रखा। अमेलिया केर ने सुने लूस और तुमी सेखुखुने पर लगातार चौके जड़ते हुए रन गति तेज की। इसके बाद बूक हॉलिडे के साथ मिलकर 73 रनों की अहम साझेदारी की। अंतिम ओवरों में केर ने तेज रन बटोरते हुए टीम का स्कोर 20 ओवर में 194/6 तक पहुंचाया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से अयाबोंगा खाका और तुमी सेखुखुने ने तीन-तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही।

लिया ताहुहु और सोफी डिवाइन ने पावरप्ले में ही शीर्ष क्रम को झकझोर दिया और टीम 40 रन पर 4 विकेट गंवा बैठी। एनेरी डर्कसन ने 23 रन बनाकर संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी अमेलिया केर ने आउट कर दिया। इसके बाद कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं सका और पूरी टीम 20 ओवर में 102/9 तक ही पहुंच सकी।

कोलकाता नाइट राइडर्स ने आंद्रे रसेल के सम्मान में रिटायर की जर्सी नंबर 12

कोलकाता। आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को खास सम्मान देते हुए उनकी जर्सी नंबर 12 को रिटायर करने का ऐलान किया है। यह घोषणा टीम के प्री-सीजन इवेंट 'नाइट अनप्लग्ड 3.0' के दौरान की गई। रसेल, जिन्हें फ्रेंचाइजी ने 'इटरनल नाइट' का दर्जा दिया है, 2014 से 2025 तक केकेआर के लिए खेलते रहे और इस दौरान उन्होंने टीम को कई यादगार जीत दिलाईं।

उन्होंने 140 आईपीएल मैचों में 2651 रन बनाए और 123 विकेट लिए। वह लीग के चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने 2000 से ज्यादा रन और 100 से अधिक विकेट का दोहरा आंकड़ा हासिल किया है। रसेल केकेआर की 2014 और 2024 की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभा चुके हैं। 2019 सीजन में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर' भी चुना गया था। इसके अलावा, 2021 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 5/15 का उनका प्रदर्शन केकेआर के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा है।

केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने कहा कि रसेल का टीम के साथ लंबा और भावनात्मक रिश्ता रहा है और जर्सी नंबर 12 उनके साथ खास पहचान बन चुका है, इसलिए इसे रिटायर कर उन्हें सम्मान दिया गया। वहीं, रसेल ने इस मौके पर भावुक होते हुए कहा कि केकेआर के साथ उनका सफर बेहद खास रहा है और फ्रेंचाइजी ने इस यात्रा को यादगार बना दिया।

सरकारी आदेश: PNG उपलब्ध होने पर भी उसकी सेवा नहीं लेने वालों की LPG आपूर्ति बंद होगी

नई दिल्ली। पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की सुविधा उपलब्ध होने पर भी इसकी सेवा नहीं लेने वाले उपभोक्ताओं की घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। सरकार ने आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी है। यह कदम गैस नेटवर्क के विस्तार को तेज करने और एक ही ईंधन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण प्रमुख स्रोतों से आपूर्ति प्रभावित होने से भारत में एलपीजी की कमी की स्थिति के बीच सरकार घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पीएनजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

पीएनजी अधिक सुविधाजनक विकल्प है और इसकी आपूर्ति घरेलू उत्पादन तथा विविध स्रोतों से की जाती है। पीएनजी पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस बर्नर तक लगातार पहुंचाई जाती है, जिससे सिलेंडर की बुकिंग की आवश्यकता नहीं रहती। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 'प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन व विस्तार तथा अन्य सुविधाएं) आदेश, 2026' अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य पाइपलाइन अवसंरचना के विकास में तेजी लाना, मंजूरियों को आसान बनाना तथा एलपीजी से पीएनजी की ओर बदलाव को बढ़ावा देकर ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। इस 24 मार्च को जारी आदेश में कहा गया कि यदि पीएनजी उपलब्ध होने के बावजूद कोई परिवार इसे नहीं अपनाता है तो तीन महीने बाद एलपीजी की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। हालांकि, जहां पाइप कनेक्शन देना तकनीकी रूप से संभव नहीं है, वहां अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के आधार पर एलपीजी आपूर्ति जारी रह सकेगी। इस कदम का उद्देश्य पाइपलाइन सुविधा वाले क्षेत्रों से एलपीजी की आपूर्ति मुक्त कर उन क्षेत्रों में भेजना है जहां यह अवसंरचना उपलब्ध नहीं है। साथ ही वैश्विक आपूर्ति व्यवधान, खाड़ी क्षेत्र में द्रवीकरण संयंत्रों को नुकसान और होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी अवरोध के बीच ईंधन विविधीकरण को बढ़ावा देना भी है।

इस आदेश पर टिप्पणी करते हुए तेल सचिव नीरज मित्तल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, " व्यवसाय सुगमता सुधारों के माध्यम से संकट को अवसर में बदला गया है।" आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी यह आदेश पाइपलाइन अवसंरचना को तेजी से विकसित करने के लिए मंजूरियों को आसान बनाने, शुल्कों का मानकीकरण करने और समयबद्ध अनुमति सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। तेजी से क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों को निर्धारित समयसीमा के भीतर मार्ग-अधिकार (राइट ऑफ वे) या अन्य अनुमतियां देनी होंगी, अन्यथा उन्हें स्वीकृत माना जाएगा। इस आदेश में अधिकारियों को निर्दिष्ट शुल्कों से अधिक शुल्क लगाने से भी प्रतिबंधित किया गया है।

आवासीय क्षेत्रों में प्रवेश नियंत्रित करने वाली इकाइयों को तीन कार्य दिवस के भीतर अनुमति देनी होगी और अंतिम चरण की पीएनजी संपर्क 48 घंटे के भीतर प्रदान की जाएगी। ऐसे क्षेत्रों में पाइपलाइन संपर्क के आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा। आदेश में भूमि पहुंच से जुड़े विवादों के समाधान के लिए नामित अधिकारियों को दीवानी अदालत जैसी शक्तियां देने का भी प्रावधान है, ताकि आवश्यक होने पर मार्ग-अधिकार प्रदान किया जा सके। अधिकृत इकाइयों को मंजूरी मिलने के चार महीने के भीतर पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू करना होगा, अन्यथा उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है जिसमें विशेष अधिकार समाप्त किया जाना भी शामिल है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) को इस आदेश के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। यह मंजूरियों, अस्वीकृतियों तथा अनुपालन की निगरानी करेगा। यदि किसी आवासीय परिसर में पीएनजी पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रवेश नियंत्रित करने वाली इकाइयां मार्ग-अधिकार या उपयोग की अनुमति नहीं देती हैं, तो उन्हें नोटिस दिया जाएगा और तीन महीने बाद तेल विपणन कंपनियां एलपीजी की आपूर्ति बंद कर देंगी।

आदेश में कहा गया कि यदि अधिकृत इकाई द्वारा पाइपलाइन बिछाने के बाद भी परिवार पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं करता, तो " ऐसे पते पर एलपीजी की आपूर्ति सूचना की तारीख से तीन महीने बाद बंद कर दी जाएगी।" यदि अधिकृत इकाई यह प्रमाणित करती है कि किसी परिवार को तकनीकी कारणों से पीएनजी कनेक्शन देना संभव नहीं है, तो एलपीजी आपूर्ति बंद नहीं की जाएगी। अधिकृत इकाई को तकनीकी असंभवता के कारणों का रिकॉर्ड रखना होगा और जैसे ही पीएनजी उपलब्ध कराना संभव होगा, एनओसी वापस ले लिया जाएगा।

रुपया 29 पैसे टूटकर 94.05 प्रति डॉलर के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर

मुंबई। रुपया बुधवार को 29 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 94.05 (अस्थायी) पर आ गया। विदेशी पूंजी की भारी निकासी और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव से निवेशक चिंतित हैं। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, डॉलर के कमजोर रुख और घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक धारणा के बावजूद स्थानीय मुद्रा को कोई राहत नहीं मिल सकी। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, डॉलर के मुकाबले 93.94 पर खुला।

डॉलर के मुकाबले 93.86 से 94.08 की सीमा में कारोबार करने के बाद अंततः यह 94.05 (अस्थायी) के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ जो पिछले बंद भाव से 29 पैसे की गिरावट है। रुपया मंगलवार को 23 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 93.76 पर बंद हुआ था। फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स एलएलपी के कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार भंसाली ने कहा, "... हमें उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक चालू वित्त वर्ष में इसे 94 के स्तर पर रखने की कोशिश करेगा और संभवतः इसे 93.30 से 92.80 तक नीचे ले जाएगा।" उन्होंने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपये का हाजिर भाव 93.25 से 94.25 के बीच रहने के आसार हैं। इस बीच, दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 99.26 पर रहा।

घरेलू शेयर बाजारों सेंसेक्स 1,205 अंक या 1.63 प्रतिशत चढ़कर 75,273.45 अंक पर जबकि निफ्टी 394.05 अंक या 1.72 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,306.45 अंक पर बंद हुआ। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 4.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 99.97 डॉलर प्रति बैरल रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को शुद्ध बिकवाल रहे और उन्होंने 8,009.56 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

कच्चे तेल के दाम में नरमी से शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी, सेंसेक्स 1,205 अंक चढ़ा

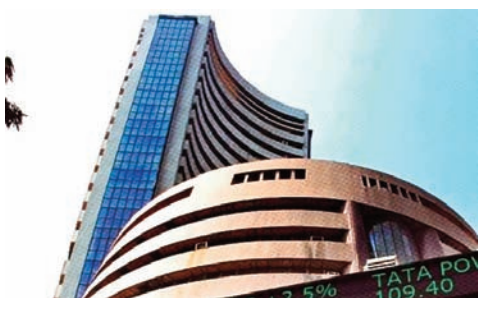

मुंबई। स्थानीय शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 1,205 अंक चढ़ गया, जबकि एनएसई निफ्टी में 394 अंक की तेजी रही। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद के बीच कच्चे तेल के दाम में कमी और वैश्विक बाजारों में मजबूती के साथ घरेलू शेयर बाजार बढ़त में रहे। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 1,205 अंक यानी 1.63 प्रतिशत बढ़कर 75,273.45 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 1,781.31 अंक चढ़कर 75,849.76 अंक पर पहुंच गया था। पचास शेयरों पर आधारित एनएसई निफ्टी 394.05 अंक यानी 1.72 प्रतिशत बढ़कर 23,306.45 अंक पर बंद हुआ।

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में से अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो, टाइटन, इंटरग्लोब एविएशन और ट्रेंट प्रमुख रूप से लाभ में रहीं। दूसरी तरफ नुकसान में रहने वाले शेयरों में टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 5.07 प्रतिशत टूटकर 99.19 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लि. के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, "वैश्विक जोखिम धारणा में सुधार और शांति की उम्मीद बढ़ने से शेयर बाजारों में तेजी बनी रही। अमेरिका और ईरान के बयान में विरोधाभास के बावजूद, दोनों देशों के बीच संभावित राजनयिक प्रगति के कारण कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर से नीचे आ गईं, जिसका बाजार ने स्वागत किया।" एशिया के अन्य बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग बढ़त के साथ बंद हुए। यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर कारोबार में तेजी का रुख था। अमेरिकी बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए।

शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 8,009.56 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 5,867.15 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। सेंसेक्स मंगलवार को 1,372.06 अंक बढ़कर 74,068.45 अंक पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 399.75 अंक चढ़कर 22,912.40 अंक पर रहा था।

ईंधन की कोई कमी नहीं, अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में खरीदारी से बचें: तेल कंपनियां

नई दिल्ली। सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार को कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर विश्वास न करने तथा घबराहट में ईंधन खरीदने से बचने की अपील की। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी 'इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन' (आईओसी) ने कहा, "पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है।" कंपनी ने बताया कि उसके पेट्रोल पंप पर्याप्त ईंधन से भरे हैं और पूरी तरह संचालित हैं।

आईओसी ने आगाह किया कि अफवाहें अनावश्यक चिंता पैदा कर सकती हैं और सामान्य आपूर्ति व्यवस्था को बाधित कर सकती हैं। कंपनी ने लोगों से घबराहट में खरीदारी से बचने और केवल सत्यापित जानकारी पर भरोसा करने को कहा है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने कुछ क्षेत्रों में ईंधन की कमी की खबरों को "पूरी तरह निराधार" बताया और कहा कि पूरे देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। कंपनी ने कहा कि भारत पेट्रोल एवं डीजल का शुद्ध निर्यातक है और उसके पास कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल तथा विमानन ईंधन (एटीएफ) का पर्याप्त भंडार है। आपूर्ति श्रृंखला बिना किसी व्यवधान के सुचारु रूप से जारी है। बीपीसीएल ने कहा कि कंपनी पूरी तरह संचालित है और निर्बाध ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने भी कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति स्थिर है तथा भंडार पर्याप्त है। कंपनी ने ग्राहकों को अफवाहों से गुमराह न होने एवं घबराहट में खरीदारी न करने की सलाह देते हुए कहा कि वे सामान्य खपत 'पैटर्न' बनाए रखें।

एचपीसीएल ने अपने नेटवर्क में निर्बाध और सुचारु ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण कच्चे तेल, एलएनजी और एलपीजी की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हुई हैं। हालांकि विविध स्रोतों से आयात के कारण भारत पश्चिम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अमेरिका से पर्याप्त कच्चा तेल हासिल करने में सफल रहा है। कतर में भारत के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता की गैस सुविधाएं युद्ध से प्रभावित होने के कारण द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति में बाधा आई है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं और सीएनजी (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) को प्राथमिकता दी गई जबकि उर्वरक संयंत्र जैसे औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति कुछ हद तक सीमित की गई है।

युद्ध का सबसे अधिक असर एलपीजी पर पड़ा है, क्योंकि देश अपनी कुल मांग का लगभग 60 प्रतिशत आयात से पूरा करता है। इसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है, जहां से आपूर्ति प्रभावित हुई है। इस स्थिति में सरकार ने घरेलू रसोई गैस आपूर्ति को प्राथमिकता दी और होटल-रेस्तरां जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए एलपीजी उपयोग को कम से कम आधा कर दिया गया है।

क्रेड ने 5,000 रुपये तक के यूपीआई भुगतान के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया शुरू

नई दिल्ली। वित्तीय प्रौद्योगिकी मंच क्रेड के उपयोगकर्ता अब 5,000 रुपये तक के यूपीआई भुगतान के लिए चेहरे या 'फिंगरप्रिंट' के माध्यम से लेनदेन को अधिकृत कर सकेंगे। कंपनी ने बुधवार को बयान में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के सहयोग से विकसित यह सुविधा आईओएस और एंड्रॉयड दोनों उपकरणों पर उपलब्ध है। यह प्रमाणीकरण व्यवस्था मंच पर होने वाले सभी यूपीआई आधारित लेनदेन पर लागू होगी जिनमें क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान, यूटिलिटी बिल, व्यापारिक लेनदेन और व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) हस्तांतरण शामिल हैं। क्रेड ने कहा, " 5,000 रुपये तक के लेनदेन के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आईओएस तथा एंड्रॉयड दोनों पर उपलब्ध है। यह सुविधा सदस्यों को अपने उपकरणों (आईओएस व एंड्रॉयड) पर उपलब्ध प्रमाणीकरण प्रणाली का सुरक्षित रूप से उपयोग करने में सक्षम बनाती है, जो नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुरूप है।" कंपनी के अनुसार, यह सुविधा 'पिन' उजागर होने से होने वाली धोखाधड़ी के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा परत प्रदान करती है और गलत या गलत टाइप किए गए पिन की स्थिति में होने वाली समस्याओं को रोककर लेनदेन की विश्वसनीयता बढ़ाती है।

धुरंधर की सफलता के बाद अब 'बादशाह' की सवारी करेंगी सौम्या टंडन

मुंबई। अभिनेत्री सौम्या टंडन इन दिनों स्पाई एक्शन फिल्म 'धुरंधरः द रिवेंज' को लेकर सुर्खियों में छाई हैं। इस बीच, अभिनेत्री ने अपने नए शौक का खुलासा किया और बताया कि उन्होंने उसकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी हैं। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया कि उन्हें घुड़सवारी का काफी शौक था, जिसकी उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। फिल्म की सफलता के बाद सौम्या अब अपनी नई रुचि पर फोकस कर रही हैं। घुड़सवारी उनके लिए न सिर्फ नया शौक है बल्कि एक सपने को पूरा करने की दिशा में पहला कदम भी है। सौम्या ने कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं। इसमें वे घोड़ों के साथ नजर आ रही हैं। वहीं, कुछ तस्वीरों में वे घुड़सवारी सीखते हुए भी दिख रही हैं। सौम्या ने लिखा, "पहला दिन और पहली घुड़सवारी की क्लास।" अभिनेत्री ने बताया कि उन्हें बचपन से ही घोड़े बहुत पसंद रहे हैं। उन्होंने लिखा, "घोड़े बहुत सुंदर और नाजुक जानवर होते हैं। मैं हमेशा उनसे आकर्षित रही हूं। मैं बचपन में एक बड़े फार्म का सपना देखती थी, जहां खूबसूरत घोड़े और कुत्ते हों। मैं खुद उन घोड़ों पर सवारी करते हुए खुद को देखती थी।" सौम्या ने लिखा, "पहला दिन थोड़ा मुश्किल रहा, लेकिन मैंने घुड़सवारी सीखना शुरू कर दिया है, तो पहला दिन काफी खतरनाक और थकाऊ था। मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, लेकिन इस क्लास में मुझे एक नया दोस्त मिल गया। वह दोस्त है एक सुंदर सफेद घोड़ा, जिसका नाम 'बादशाह' है।" सौम्या ने मजाकिया अंदाज में बताते हुए लिखा, "मैंने बादशाह से बहुत बातें कीं। सच कहूं तो वह बहुत अच्छा सुनने वाला था या शायद उसके पास और कोई चारा नहीं था, लेकिन उसने मेरी सारी बातें ध्यान से सुनीं।

बॉलीवुड पर बरसीं अमीषा पटेल

बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल ने फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' की जमकर तारीफ करते हुए निर्देशक आदित्य धर की सराहना की। सोशल मीडिया पर किए गए अपने पोस्ट में अमीषा ने कहा कि आज के दौर में जहां कलाकारों का चयन 'इंस्टाग्राम फॉलोअर्स' के आधार पर किया जा रहा है, वहीं आदित्य धर ने सिर्फ प्रतिभाशाली कलाकारों को मौका देकर एक मिसाल पेश की है। अमीषा ने बॉलीवुड पर निशाना साधते हुए लिखा कि इंडस्ट्री को यह समझने की जरूरत है कि 'धुरंधर 2' एक 'फिल्म' है, न कि सिर्फ एक 'प्रोजेक्ट'। उन्होंने कहा कि आदित्य धर ने असली कलाकारों को कास्ट किया है, न कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाले चेहरों को। उनके इस बयान ने फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग के मौजूदा ट्रेंड पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले आलिया भट्ट, कंगना रनौत, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, महेश बाबू और रजनीकांत जैसे कई बड़े सितारे भी फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। फिल्म की स्टारकास्ट भी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। मुकेश छाबड़ा द्वारा की गई कास्टिंग में रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ कई प्रतिभाशाली अभिनेताओं को भी अहम भूमिकाएं दी गई हैं। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म शानदार प्रदर्शन कर रही है और भारतीय बाजार में 570 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है, जिससे यह साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई है।

फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग को लेकर छेड़ी नई बहस

अब 'वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' 28 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी

बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा की आगामी फिल्म 'वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। निर्माताओं ने फिल्म की नई रिलीज तारीख का ऐलान कर दिया है। पहले यह फिल्म 15 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाकर 28 अगस्त कर दिया गया है। खास बात यह है कि फिल्म रक्षाबंधन के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी। निर्माताओं ने फिल्म का नया पोस्टर जारी करते हुए इसकी रिलीज डेट की पुष्टि की। इस फिल्म में पहली बार सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ तमन्ना भाटिया नजर आएंगी, जिससे दर्शकों के बीच उत्साह और भी बढ़ गया है। फिल्म का निर्देशन दीपक मिश्रा और अरुणभ कुमार ने किया है, जबकि निर्माण की जिम्मेदारी एकता कपूर ने संभाली है। 'वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' का निर्माण बालाजी मोशन पिक्चर्स और द वायरल फीवर (टीवीएफ) के सहयोग से किया गया है। फिल्म की शूटिंग मध्य भारत के घने जंगलों में की गई है और इसकी कहानी गुप्त मंदिरों व प्राचीन लोककथाओं पर आधारित बताई जा रही है। थिएटर रिलीज के बाद यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर भी उपलब्ध होगी।

'पेड्डी' की शूटिंग में घायल हुए राम चरण

साउथ सुपरस्टार राम चरण अपनी आगामी फिल्म 'पेड्डी' की शूटिंग के दौरान घायल हो गए हैं, जिससे उनके फैंस चिंता में आ गए थे। हालांकि, अब उनकी टीम ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए बताया है कि अभिनेता पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनकी आंखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यह हादसा 24 मार्च को एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक, राम चरण को एक आंख के ऊपर चोट लगी थी, जिसके चलते उन्हें चार टांके लगवाने पड़े। टीम के सूत्र ने स्पष्ट किया कि चोट आंख में नहीं, बल्कि उसके ऊपर लगी है और अभिनेता की आंख पूरी तरह सुरक्षित है। इस खबर के बाद फैंस ने राहत की सांस ली है। चोट लगने के बावजूद राम चरण ने शूटिंग से ब्रेक नहीं लिया और वह जल्द ही सेट पर लौट आए। 'पेड्डी' एक स्पोर्ट्स-ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण वृद्धि सिनेमाज के बैनर तले किया जा रहा है। गौरतलब है कि फिल्म का निर्देशन बुची बाबू सना कर रहे हैं और इसमें जाह्नवी कपूर भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म में ए.आर. रहमान का संगीत होगा और इसमें शिव राजकुमार, जगपति बाबू और दिव्येंदु भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। यह फिल्म 30 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि इसका टीजर 27 मार्च को राम चरण के जन्मदिन पर जारी किए जाने की संभावना है।